सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 160, नई दिल्ली, सोमवार 18 अगस्त 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए जीवन को समझना जरूरी है।

03 वोट चोरी के लग रहे आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान

06 ग्रामीण विकास को गति देती पंचायतें

08 झारखंड के गोड्डा में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से चार लोगों की मौत

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

पिंकी कुंडू सह संपादक परिवहन विशेष

सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर (UDHR) अनुच्छेद 22) और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (आईसीईएससीआर (ICESCR) अनुच्छेद 9) में मान्यता दी गई है। इसका अर्थ है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग बेरोज़गारी, बीमारी, विकलांगता, वृद्धावस्था या अन्य अनियंत्रित परिस्थितियों में सुरक्षित रहें।

इसमें पेंशन, बेरोज़गारी भत्ता, स्वास्थ्य सेवाएँ और सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुँच शामिल है, ताकि कोई भी व्यक्ति चरम गरीबी या विपन्नता में न रहे। भारत में, मनरेगा (रोज़गार गारंटी), वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य सेवा), और पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा) जैसी योजनाएँ इस अधिकार को पूरा करने का हिस्सा हैं।

2. अपमानजनक व्यवहार या दंड से मुक्ति यह अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर अनुच्छेद 5) और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (आईसी सीपीआर अनुच्छेद 7) से लिया गया है।

यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड का शिकार नहीं होना चाहिए।

अपमानजनक व्यवहार का अर्थ है – ऐसा कोई भी कार्य जो व्यक्ति को अपमानित करे, उसकी गरिमा छीन ले या उसे "मानव से कमतर" समझे। यह सिद्धांत केवल जेलों या पुलिस हिरासत में ही नहीं, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं, अस्पतालों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक नीतियों में भी लागू होता है।

उदाहरणः यदि हाशिए पर खड़े समुदायों को सामाजिक लाभ से वंचित किया जाए या मदद देते समय उन्हें अपमानित किया जाए, तो यह अपमानजनक व्यवहार माना जाएगा।

3. दोनों के बीच संबंध यदि लोगों को सामाजिक सुरक्षा से वंचित किया जाए या उन्हें गरिमा के बिना जीवन जीने को मजबूर किया जाए, तो यह स्वयं एक प्रकार का अपमानजनक व्यवहार है। उदाहरणः यदि बुज़ुर्गों को पेंशन देने के बजाय भिक्षा मांगने पर मजबूर किया जाए, या गरीबों को राशन वितरण के समय अपमानित किया जाए, तो यह सामाजिक सुरक्षा के अधिकार और गरिमा के अधिकार दोनों का उल्लंघन है।

संक्षेप में:-

1. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार = ज़रूरत के समय सुरक्षा।
2. अपमानजनक व्यवहार या दंड से मुक्ति = गरिमा और मानवीय व्यवहार की गारंटी।

दोनों मिलकर यह दर्शाते हैं कि सच्ची सामाजिक सुरक्षा केवल आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि सम्मान, गरिमा और निष्पक्षता के साथ दी गई मदद है।

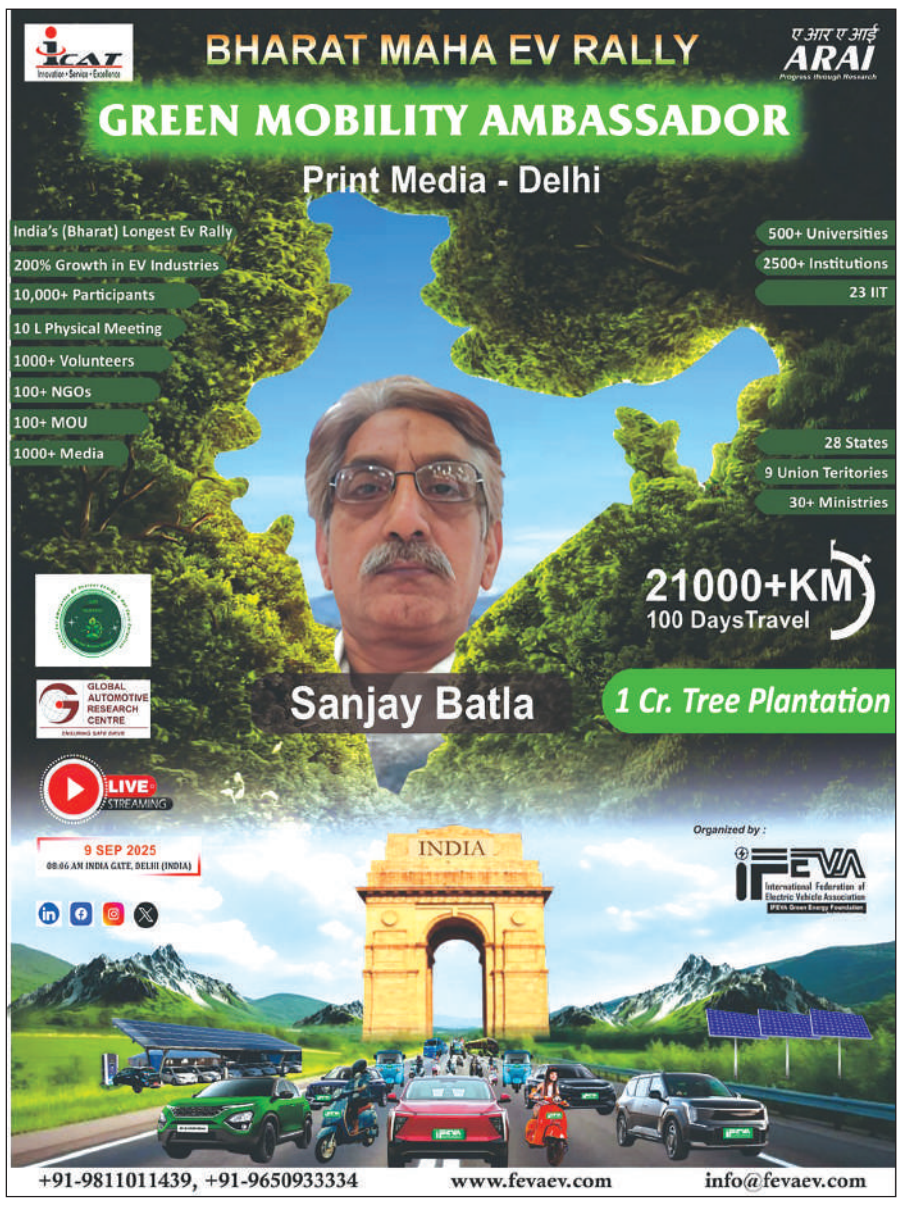

एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए तय किया सीपी राधाकृष्णन का नाम

पिंकी कुंडू सह संपादक परिवहन विशेष

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रविवार को अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने बताया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुना गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।

घोषणा के बाद जे. पी. नड्डा ने कहा कि, "एनडीए की ओर से यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। हमारी कोशिश है कि चुनाव निर्विरोध हो और विपक्षी दलों को भी इस पर सहमति बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।"

राजनीति में चार दशक का अनुभव

सी. पी. राधाकृष्णन का राजनीतिक करियर चार दशकों से अधिक लंबा है। वे मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं और भाजपा संगठन में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें पार्टी के एक अनुभवी और व्यवहारकुशल नेता के तौर पर जाना जाता है।

राज्यपाल के रूप में राधाकृष्णन का अनुभव

राधाकृष्णन इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले वे झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उनके प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है।

निर्विरोध चुनाव होने की पूरी संभावना .

एनडीए को विश्वास है कि राधाकृष्णन निर्विरोध चुने जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने कहा कि विपक्षी दलों से भी इस नाम पर समर्थन मांगा जाएगा ताकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आम सहमति से संपन्न हो सके। यदि निर्विरोध निर्वाचित होते हैं, तो सी. पी. राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति बन जाएंगे।

सी. पी. राधाकृष्णन : एक नज़र में

पूरा नाम : सी. पी. राधाकृष्णन
जन्मस्थान : तमिलनाडु
राजनीतिक करियर : 40 वर्ष से अधिक का अनुभव
पद : वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल

पूर्व में झारखंड के राज्यपाल

पहचान : भाजपा के वरिष्ठ और अनुभवी नेता, संगठनात्मक मजबूती के लिए जाने जाते हैं

विशेषता : सर्वस्वीकार्य छवि, प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव

परिवहन उद्योग की चुनौतियों पर खुली चर्चा

मान-सम्मान और स्वाभिमान के माहौल में ही संभव है सुचारु परिवहनःडॉ यादव

परिवहन विशेष न्यूज

राउरकेलाः राउरकेला गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की एक अहम बैठक रविवार को ब्राह्मणी क्लब में आयोजित हुई। बैठक में परिवहन उद्योग से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव सहित जगदीश हरित, अश्विन शाह, राममेहर शर्मा, नरेश अग्रवाल, मानस मोहंती, नंदकिशोर सिंह, शंकर लाल शर्मा, जसविंदर सिंह गोल्डी, चरणजीत सिंह, मोहम्मद सलीम, राकेश जायसवाल मुन्ना, श्याम प्रसाद, रामाग्या प्रसाद, उमेश सिंह, अमित खंडेलवाल, राजेश श्रीवास्तव, राजकुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे।

चर्चा के दौरान विभिन्न लोडिंग प्वाइंट्स पर मनमानी, डिटेंशन चार्ज, माल मिलावटी, बिना एसोसिएशन की सदस्यता के आपूर्ति कराने, पार्किंग की समस्या जैसी गंभीर चुनौतियों पर विचार-विमर्श हुआ। अगली रणनीति तय करने के लिए 5 सितंबर को फिर बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

डॉ. राजकुमार यादव ने कहा कि— "बाजार और मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण है मान-सम्मान और स्वाभिमान। भयमुक्त और खुले वातावरण में कार्य करना ही हमारी प्राथमिकता होगी।" उन्होंने सभी सदस्यों के समर्थन के लिए आभार जताया और ट्रांसपोर्टरों के हित में पूरी निष्ठा से कार्य करने का आश्वासन दिया। सभा के अंत में मोहम्मद सलीम ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर, एनसीआर वालों को पीएम मोदी की सौगात, UER-II और द्वारका एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर वालों को अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली भाग की सौगात दी। 11000 करोड़ रुपये की लागत से बने ये प्रोजेक्ट दिल्ली को जाम मुक्त करने और यातायात को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे से सिंघु बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट का 2 घंटे का सफर अब 40 मिनट में पूरा होगा।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (17 अगस्त) को अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-II) और द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka Expressway) के दिल्ली भाग का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे।

दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले इन दो हाई स्पीड कॉरिडोर्स के लोकार्पण से लोगों की आवाजाही आसान होगी। लगभग 11,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार दोनों सड़क परियोजनाओं से एनसीआर के अलावा देश के अन्य हिस्सों में यातायात संचालन बेहतर होगा।

अब द्वारका एक्सप्रेसवे से सिंघु बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर 40 मिनट में पूरा होगा। पहले इस सफर में 2 घंटे का वक्त लगता था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली को जाम और प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य है। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है।

बक्करवाला मुंडका टोल के पास से रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते, पीएम मोदी नेतृत्व में पिछले 5 महीनों के प्रशासनिक अनुभव के आधार पर, मैं कह सकती हूं कि आप दूरदर्शी नेता हैं, जिनकी सोच में भारत का प्रत्येक नागरिक शामिल हैं। जिनकी नीतियां सुनिश्चित करती हैं कि भारत का प्रत्येक राज्य बराबर का भागीदार है। जिनके संकल्प से भारत का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित महसूस करता है। आप वो ताकत हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है।

एक नजर में द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट

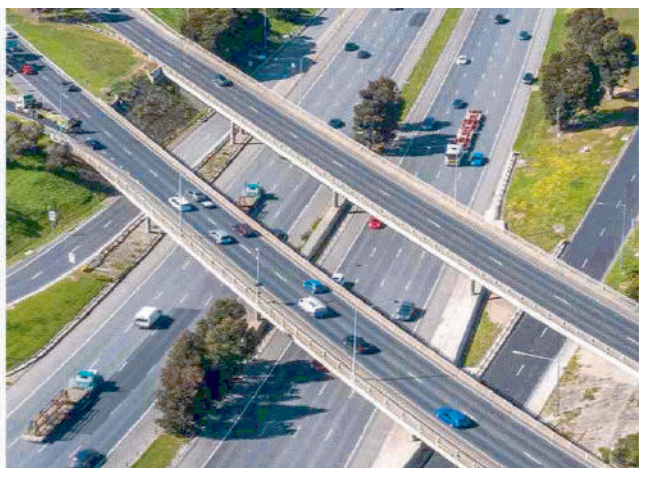

इसे कुल चार पैकेज में बांटा गया है। दो पैकेज गुरुग्राम इलाके में और दो पैकेज दिल्ली इलाके में हैं।

गुरुग्राम के दोनों पैकेज के निर्माण की जिम्मेदारी एलएंडटी नामक कंपनी के पास है।

दिल्ली के दोनों पैकेज की जिम्मेदारी जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक कंपनी के पास है।

गुरुग्राम में पहला पैकेज खेड़कीदौला टोल प्लाजा के नजदीक से बसई-धनकोट के नजदीक तक 8.76 किलोमीटर का है।

गुरुग्राम में दूसरा पैकेज बसई-धनकोट के नजदीक से गुरुग्राम-दिल्ली सीमा तक 10.2 किलोमीटर का है।

दिल्ली में पहला पैकेज गुरुग्राम-दिल्ली सीमा से बिजवासन तक लगभग 4.20 किलोमीटर का है।

दिल्ली में दूसरा पैकेज बिजवासन से महिपालपुर में शिवमूर्ति तक 5.90 किलोमीटर का है।

प्रोजेक्ट का 18.9 किलोमीटर हिस्सा गुरुग्राम में जबकि बाकी 10.1 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में पड़ता है।

प्रोजेक्ट का 23 किलोमीटर भाग एलिवेटेड और लगभग चार किलोमीटर भूमिगत (टनल) बनाया गया है।

द्वारका एक्सप्रेस-वे से पालम एयरपोर्ट तक जाने के लिए 3.6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है।

द्वारका एक्सप्रेस-वे देश का पहला अर्बन एक्सप्रेस-वे है।

इसका एलिवेटेड हिस्सा सिंगल पिलर के ऊपर बनाया गया है।

निर्माण में दो लाख एमटी स्टील का इस्तेमाल हुआ है जो एफिल टावर के निर्माण की तुलना में 30 गुना अधिक है।

20 लाख सीयूएम कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा जो बुर्ज खलीफा की तुलना में छह गुना अधिक है।

प्रोजेक्ट के लिए 12 हजार से अधिक पेड़ों का ट्रांसप्लांट किया गया है।

इसके चालू होने से दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर ट्रैफिक का दबाव लगभग 25 प्रतिशत कम हुआ है।

निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर से ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए गुरुग्राम में खेड़कीदौला टोल प्लाजा के नजदीक से लेकर दिल्ली के महिपालपुर में शिवमूर्ति के सामने तक लगभग नौ हजार करोड़ रुपये की लागत से द्वारका एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया गया है।

एक नजर में यूईआर-दो

यह दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक 75.71 किलोमीटर लंबा है।

दिल्ली के लिए तीसरे रिंग रोड के रूप में विकसित यह 6-लेन का एक्सेस-कंट्रोल एक्सप्रेसवे है।

यह बवाना, नरेला, कंझावला, मुंडका, द्वारका, सोनीपत, रोहतक, जींद, बहादुरगढ़ सहित कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ा है।

इसे द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे सहित कई राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा गया है।

मुख्य उद्देश्य दिल्ली में ट्रैफिक जाम को कम करना और विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में बेहतर बनाना है।

इसे तीसरी रिंग रोड के रूप में डिजाइन किया गया है, जो इनर और आउटर रिंग रोड को जोड़ता है।

कई इलाकों के जुड़ने से आने वाले समय में यूईआर-दो बड़ा लाजिस्टिक हब के रूप में दिखाई देगा।

यूईआर-दो के बारे में ये भी जानिए

वर्ष 2000 में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत दिल्ली के तीसरे रिंग रोड के रूप में डिजाइन किया गया था।

यह 27 फ्लाईओवर, 26 छोटे पुल और 17 सबवे से सुसज्जित एक्सप्रेसवे है।

यह एक एक्सेस-कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसमें चौराहों पर ऊंचे फ्लाईओवर और स्थानीय यातायात के लिए अलग सर्विस लेन हैं।

इसे ग्रीन रोड के रूप में भी विकसित किया गया है। इसमें गाजीपुर लैंडफिल से 20 लाख टन कचरे का उपयोग किया गया है।

यह ई-हाईवे बनने वाले पहले राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है। इसके ऊपर ई-बसों, ई-ट्रालियों और ई-कारों को चलाने की योजना है।

चार-युग और उनकी विशेषताएं

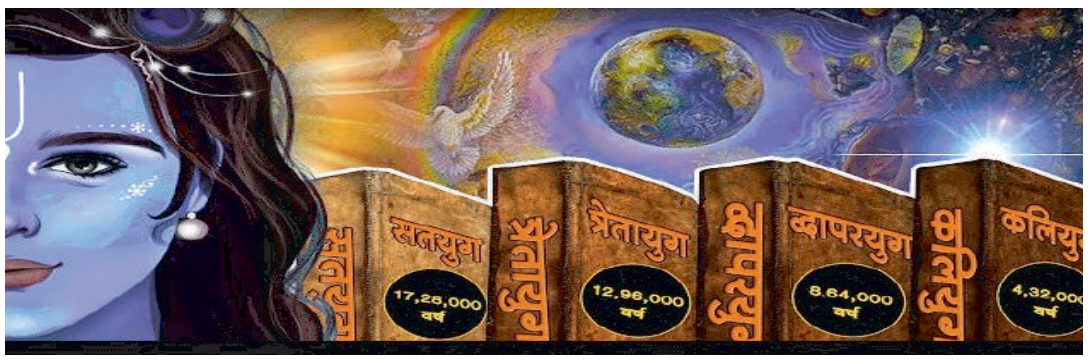

'युग' शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल-अवधि। जैसे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग आदि।

यहाँ हम चारों युगों का वर्णन करेंगें। युग वर्णन से तात्पर्य है कि उस युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु, ऊँचाई, एवं उनमें होने वाले अवतारों के बारे में विस्तार से परिचय देना। प्रत्येक युग के वर्ष प्रमाण और उनकी विस्तृत जानकारी कुछ इस तरह है -

सत्ययुग

यह प्रथम युग है इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है -

इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि – 17,28,000 वर्ष होती है।

इस युग में मनुष्य की आयु – 1,00,000 वर्ष होती है ।

मनुष्य की लम्बाई – 32 फिट (लगभग) [21 हाथ]

सत्ययुग का तीर्थ – पुष्कर है ।

इस युग में पाप की मात्र – 0 विश्वा अर्थात (0%) होती है ।

इस युग में पुण्य की मात्रा – 20 विश्वा अर्थात (100%) होती है ।

इस युग के अवतार – मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह (सभी अमानवीय अवतार हुए) है ।

अवतार होने का कारण – शंखासुर का वध एंव वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण, हरिण्याक्ष दैत्य का वध, हिरण्यकश्यपु का वध एवं प्रह्लाद को सुख देने के लिए।

इस युग की मुद्रा – रत्नमय है ।

इस युग के पात्र – स्वर्ण के है ।

त्रेतायुग

यह द्वितीय युग है इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है –

इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि – 12,96,000 वर्ष होती है ।

इस युग में मनुष्य की आयु – 10,000 वर्ष होती है ।

मनुष्य की लम्बाई – 21 फिट (लगभग) [14 हाथ]

त्रेतायुग का तीर्थ – नैमिषारण्य है ।

इस युग में पाप की मात्रा – 5 विश्वा अर्थात (25%) होती है ।

इस युग में पुण्य की मात्रा – 15 विश्वा अर्थात (75%) होती है ।

इस युग के अवतार – वामन, परशुराम, राम (राजा दशरथ के घर)

अवतार होने के कारण – बलि का उद्धार कर पाताल भेजा, मदान्ध क्षत्रियों का संहार, रावण-वध एवं देवों को बन्धनमुक्त करने के लिए ।

इस युग की मुद्रा – स्वर्ण है ।

इस युग के पात्र – चाँदी के है ।

द्वापरयुग

यह तृतीय युग है इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है –

इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि – 8.64,000 वर्ष होती है ।

इस युग में मनुष्य की आयु - 1,000 होती है ।

मनुष्य लम्बाई – 11 फिट (लगभग) [7 हाथ]

द्वापरयुग का तीर्थ – कुरुक्षेत्र है ।

इस युग में पाप की मात्रा – 10 विश्वा अर्थात (50%) होती है ।

इस युग में पुण्य की मात्रा – 10 विश्वा अर्थात (50%) होती है ।

इस युग के अवतार – कृष्ण, (देवकी के गर्भ से एंव नंद के घर पालन-पोषण), बुद्ध (राजा के घर) ।

अवतार होने के कारण – कंसादि दुष्टो का संहार एंव गोपों की भलाई, दैत्यो को मोहित करने के लिए ।

इस युग की मुद्रा – चाँदी है ।

इस युग के पात्र – ताम्र के हैं ।

कलियुग

यह चतुर्थ युग है इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है –

इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि – 4,32,000 वर्ष होती है ।

इस युग में मनुष्य की आयु – 100 वर्ष होती है ।

मनुष्य की लम्बाई – 5.5 फिट (लगभग) [3.5 हाथ]

कलियुग का तीर्थ – गंगा है ।

इस युग में पाप की मात्रा – 15 विश्वा अर्थात (75%) होती है ।

इस युग में पुण्य की मात्रा – 5 विश्वा अर्थात (25%) होती है ।

इस युग के अवतार – कल्कि (ब्राह्मण विष्णु यश के घर) ।

अवतार होने के कारण – मनुष्य जाति के उद्धार अधर्मियों का विनाश एवं धर्म कि रक्षा के लिए।

इस युग की मुद्रा – लोहा है।

इस युग के पात्र – मिट्टी के है।

हिमालय का महाकुंभ जो पूरी पैदल यात्रा होती है, आयोजित होती है हर बारा वर्ष

नंदा राज जात यात्रा जो मा पार्वती यानी नंदा देवी के लिए समर्पित है। जिसे हिमालय का महाकुंभ भी कहते है। यह यात्रा पूरे उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में हर बारा साल बाद हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस यात्रा के पीछे ऐसी कथा है कि जब माता पार्वती जिन्हें नंदा देवी उत्तराखंड में कहते है एक समय कैलाश में माता को अपने मैत (माइके) की याद आने लगी और तब उन्होंने अपने भाइयों हीत, बिनसर और लाटू अपनी माता मैनावती और पिता राजा हिमावंत सबकी याद आ रही थी तब जब माइके में जब सबको इस चीज का आभास हुआ। तब माता के भाई हीत, बिनसर और लाटू तीनों कैलाश में आते है और माता को माइका लेकर आते है और जब माता माइका आती है तब हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया जाता है और जब बारी आती है कैलाश जाने की तब एक भव्य यात्रा होती है वही यात्रा है नंदा राज जात यात्रा।

माता के माइके आने का संकेत यह है कि गांव में का चौसिंगया खाडू यानी चार सिंग वाले भेड़ जन्म होता है वही संकेत होती है कि माता आगई माइके और यही भेड़ पूरी कैलाश यात्रा में जाता है हीत, बिनसर और लाटू के साथ और खुद इस भेड़ को कैलाश में छोड़ दिया जाता है।

यह यात्रा गढ़वाल में चमोली के नौटी गांव से शुरू होती है जिसमें माता अपनी डोली में बैठके पूरे गढ़वाल के बधानी गांव, कांसुवा (वहां के कुंवर माता का स्वागत करते है) सेम गांव, कोटि गांव, भगवती गांव, कुलसारी गांव, नंदकेसरी गांव, मुंडोली गांव, वान गांव, बेदनी बुग्याल (जहां महर्षि व्यास जी ने चार वेद लिखे), पठार नौछानी, भगवा बासा, त्रिशूली, रूपकुंड, शिला समुद्र से होमकुंड माता अपनी डोली में बैठकर अपने भक्त गण, अपने भेड़, अपने भाइयों के साथ सीधा होमकुंड से कैलाश की तरफ चली जाती है और वही कुमाऊं में माता अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत से निकल कर अपने भेड़ के साथ पूरा कुमाऊं भ्रमण करके कैलाश चली जाती है।

अब अगला राज जात अगले साल यानी 2026 के अगस्त सितंबर के बीच में होगी 2013 के आपदा के कारण नंदा राज जात 2014 में हुई थी।

जय मां नंदा राज राजेश्वरी

अरावन देवता, जिनसे होती है किन्नरोंहिंजड़ो की शादी?

हमारे देश भारत के तमिलनाडु राज्य में एक देवता अरावन की पूजा की जाती है। कई जगह इन्हे इरावन के नाम से भी जाना जाता है। अरावन हिंजड़ो के देवता है इसलिए दक्षिण भारत में हिंजड़ो को अरावनी कहा जाता है।

हिंजड़ो और अरावन देवता के सम्बन्ध में सबसे अचरज वाली बात यह है की हिंजड़े अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते है।

हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है।

अब सवाल यह उठता है की अरावन है कौन? हिंजड़े उनसे क्यों शादी रचाते है? और यह शादी मात्र एक दिन के लिए ही क्यों होती है ?

इन सभी प्रशनो का उत्तर जानने के लिए हमे महाभारत काल में जाना पड़ेगा।

अरावनअर्जुन और नाग कन्या उलुपी के पुत्र थे। अरावन महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रोपदी से शादी की एक शर्त के उल्लंघन के कारण इंद्रप्रस्थ से निष्कासित करके एक साल की तीर्थयात्रा पर भेजा जाता है।

वहाँ से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाते है जहाँ की उनकी मुलाक़ात एक विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते है।

विवाह के कुछ समय पश्चात उलूपी एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम अरावन रखा जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात अर्जुन उन दोनों को वही छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाता है।

अरावन नागलोक में अपनी माँ के साथ ही रहता है। युवा होने पर वो नागलोक छोड़कर अपने पिता के पास आता है। तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है। इसलिए अर्जुन उसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेज देता है।

महाभारत युद्ध में दी थी स्वयं की बलि महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवो को अपनी जीत के लिए माँ काली के चरणो में स्वेचिछक नर बलि हेतु एक राजकुमार की जरुरत पड़ती है।

जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता है तो अरावन खुद को स्वेचिछक नर बलि हेतु प्रस्तुत करता है लेकिन वो शर्त रखता है की वो अविवाहित नहीं मरेगा।

इस शर्त के कारण बड़ा संकट उत्पन हो जाता है क्योकि कोई भी राजा यह जानते हुए की अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जायेगी अरावन से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं होता है।

जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वंय को मोहिनी रूप में बदलकर अरावन से शादी करते है। अगले दिन अरावन स्वंय अपने हाथो से अपना शीश माँ काली के चरणो में अर्पित करता है।

अरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते है। अब चुकी श्री कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में अरावन से शादी रचाते है।

इसलिए किन्नर जो की स्त्री रूप में पुरुष माने जाते है भी अरावन से एक रात की शादी रचाते है और उन्हें अपना आराध्य देव मानते है।कूवगम तमिलनाडु में है भगवान अरावन का मंदिर ।

वैसे तो अब तमिलनाडु के कई हिस्सों में भगवान अरावन के मंदिर बन चुके है पर इनका सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर विल्लुपुरम जिले के कूवगम गाँव में है जो की Koothandavar Temple के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान अरावन के केवल शीश की पूजा की जाती है ठीक वैसे ही जैसे की राजस्थान के खाटूश्यामजी में बर्बरीक के शीश की पूजा की जाती है।

हिंजड़ो का सबसे बड़ा उत्सव कूवगम गाँव में हर साल तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा फुल मून को 18 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत होती है।

इस उत्सव में पुरे भारत वर्ष और आस पास के देशों से किन्नर इकठ्ठा होते है। पहले 16 दिन मधुर गीतों पर खूब नाच गाना होता है। किन्नर गोल घेरे बनाकर नाचते गाते है।

बीच बीच में ताली बजाते है । और हंसी खुशी शादी की तैयारी करते हैं। चारों तरफ घंटियों की आवाज उत्साही लोगों की आवाजें गूंज रही होती हैं । चारों तरफ के वातावरण को कपूर और चमेली के फूलों की खूशबू महकाती है।

17 वे दिन पुरोहित दवारा विशेष पूजा होती है और अरावन देवता को नारियल चढाया जाता है । उसके बाद आरावन देवता के सामने मंदिर के पुराहित के दवारा किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है ।

जिसे थाली कहा जाता है ।फिर अरावन मंदिर में अरावन की मूर्ति से शादी रचाते है । अतिंम दिन यानि 18 वे दिन सारे कूवगम गांव में अरावन की प्रतिमा को घूमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है।

उसके बाद दुल्हन बने किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते है साथ ही चेहरे पर किए सारे श्रृंगार को भी मिटा देते हैं । और सफेद कपड़े पहन लेते है और जोर जोर से छाती पीटते है और खूब रोते है।

जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखे भी नम हो जाती है और उसके बाद आरावन उत्सव खत्म हो जाता है । और अगले साल की पहली पूर्णिमा पर फिर से मिलने का वादा करके लोगों का अपने अपने घर को जाने कार्यक्रम शुरू हो जाता है ।।

हल्दी हर्बल चाय: स्वाद सहित उपचार

आजकल की तेज़ ज़िंदगी में हर कोई स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प ढूंढ़ रहा है। आयुर्वेद के अनुसार, हमारे किचन में ही कई ऐसी औषधियाँ छिपी होती हैं जो गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिला सकती हैं। इन्हीं में से एक है — अदरक, हल्दी और दालचीनी से बनी हर्बल चाय।

यह चाय न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि यह शरीर को डिटॉक्स करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और कई chronic diseases जैसे Diabetes, Migraine, PCOD आदि को नियंत्रित करने में मदद करती है।

कैसे बनाएं अदरक, हल्दी और दालचीनी की हर्बल चाय? आवश्यक सामग्रीः

1. 400 ml पानी
2. 1/2 चम्मच हल्दी
3. एक छोटा टुकड़ा दालचीनी
4. 1/2 चम्मच अदरक का रस

बनाने की विधिः

1. सबसे पहले 400 ml पानी को उबालें।
2. उसमें दालचीनी डालें और आंच धीमी कर दें।
3. फिर उसमें हल्दी और अदरक का रस मिलाएं।
4. 1 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं और फिर गैस बंद कर दें,
5. चाय को छानकर पी लें।

इस चाय को पीने का सही समयः

१. सुबह खाली पेट — शरीर को डिटॉक्स करने के लिए।

२. रात को सोने से पहले — बेहतर नींद और मेटाबॉलिज्म सुधार के लिए।

अदरक, हल्दी और दालचीनी की चाय के जबरदस्त फायदेः

1. वजन घटाने में मददगारः- यह चाय शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करती है। नियमित सेवन से बिना कड़ी एक्सरसाइज़ किए भी वजन में कमी देखी जा सकती है।

2. Diabetes (मधुमेह) में असरदारः- यह हर्बल चाय रक्त में शुगर लेवल को संतुलित करती है और Diabetes Type 2 के नियंत्रण में सहायक है।

3. Migraine (आधा सिर दर्द) से राहतः- जो लोग माइग्रेन से परेशान हैं, उनके लिए यह चाय सिरदर्द को कम करने में काफी असरदार होती है।

4. पाचन और गैस की समस्या में फायदेमंदः- इस चाय का सेवन पेट की गैस, अपच और एसिडिटी की समस्याओं को दूर करता है।

5. गर्भवती महिलाओं के लिए उपयोगीः- प्रेगनेंसी के दौरान Morning sickness और मतली की समस्या में यह चाय काफी आराम देती है (हालांकि डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है)।

6. मासिक धर्म के दर्द में राहतः- महिलाओं को पीरियड्स के समय होने वाले पेट दर्द और ऐंठन से राहत दिलाने में यह चाय मदद करती है।

7. शरीर को डिटॉक्स करती हैः- यह हर्बल चाय शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है।

किन रोगों में और लाभदायक है यह चाय?

1. हाई ब्लड प्रेशर (High BP)
2. शरीर में सूजन
3. PCOD/PCOS
4. गैस और एसिडिटी
5. थकान और इम्यूनिटी की कमी

विशेषज्ञ की सलाहः ₹यह चाय हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान पर आधारित है। यदि इसे नियमित रूप से लिया जाए, तो यह शरीर को रोगमुक्त और ऊर्जावान बना सकती है।₹

निष्कर्षः यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हैं और Chemical-based products से दूर रहना चाहते हैं, तो यह हर्बल चाय एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और प्राकृतिक चिकित्सा के लाभ उठाएं।

अर्थोपार्जन और आध्यात्मिकता

कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि ₹धार्मिक व्यक्ति₹ को धन से ₹विरक्ति₹ होनी चाहिए। जहाँ तक आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति का प्रश्न है, धन के प्रति अत्यधिक लगाव न रखना उचित भी है, किंत गृहस्थी की सुख-सुविधाओं के लिए, ₹धार्मिक प्रयोजनों₹ की पूर्ति के लिए ₹धन₹ अत्यधिक आवश्यक है। धन के बिना न धर्म संभव है न कर्तव्य पालन। इस दृष्टि से ₹निर्धनता₹ अभिशाप है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में धन का उतना ही महत्त्व है, जितना ईश्वर उपासना का। लक्ष्मी को परमात्मा का वामांग मानते हैं। इसलिए उपासना को तब पूर्ण समझना चाहिए जब लक्ष्मी-नारायण दोनों की प्रतिष्ठा हो। जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ का परमात्मा भी बेचैन रहता है। लक्ष्मी रहती है तो परमात्मा की प्राप्ति में सुविधा मिलती है, हमारी मान्यता इस प्रकार की होनी चाहिए।

आर्थिक दृष्टि से मनुष्य दूसरों का गुलाम बने, यह न तो उपयुक्त ही है और न परमात्मा की ही ऐसी इच्छा है। उन्होंने अपने प्रत्येक पुत्र को समान साधन दिए हैं, समान क्षमताएँ दी हैं तो उसका एक ही उद्देश्य रहा है कि आत्म-कल्याण और जीवनयापन में प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर रहे। ईश्वरनिष्ठ को निराश्रित होना उचित भी नहीं, अपनी आजीविका का प्रबंध उसे स्वयं करना चाहिए।

₹निर्धनता₹ एक प्रकार की ₹आध्यात्मिक विकृति₹ है। धन न कमाना त्याग का लक्षण नहीं। यह मनुष्य में दैवी गुणों की कमी का परिचायक है। हर व्यक्ति को विशुद्ध धार्मिक भावना से अर्थोपार्जन करना चाहिए। यह क्रिया आत्म-विकास के अंतर्गत ही आती है। 'पीस, पावर एंड प्लेन्टी' (शांति, शक्ति और समृद्धि) नामक पुस्तक के रचयिता श्री ओरिसन मार्डन ने लिखा है- ₹जो दरिद्री होते हैं उनमें न आत्म-विश्वास होता है और न श्रद्धा। लोग अपनी स्थिति बदल सकते हैं पर उन्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा करना आना चाहिए। आशा, साहस, उत्साह और कर्मशीलता के द्वारा कोई भी व्यक्ति श्री संपन्न बन सकता है।

धन को सुख का साधन मानकर उसे ₹ईमानदारी₹ और ₹परिश्रम₹ के द्वारा कमाया जाए तो वह आत्म-विकास में भी सहायक होता है। धन प्राप्ति का एक दोष भी है- होता अनावश्यक ₹लोभ₹ । वित्तेषणा के कारण लोग अनुचित तरीकों से धन कमाना चाहते हैं। बेईमानी के द्वारा कमाया हुआ धन मनुष्य को व्यसनों की ओर आकर्षित करता है। जुआ, सट्टा, लाटरी, नशा, वेश्यावृत्ति में धन का अपव्यय करने वाले प्रायः सभी अनुचित तरीकों से धनार्जन करते हैं।,इस प्रकार की कमाई मनुष्य की दुर्गति करती है। इस प्रकार का धन हेय कहा गया है और उस ₹धन₹ से ₹निर्धन₹ होना अच्छा बताया गया है।

अर्थोपार्जन में जिन आध्यात्मिक गुणों का समावेश होना चाहिए, शास्त्रकार ने उन्हें बड़े आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया है। लक्ष्मी को वे देवी मानते हैं। उन्हें कमल पुष्प पर आसीन, ऊपर से फूलों की वर्षा होती हुई दिखाया गया है। ₹कमल₹ ₹पवित्रता₹ और ₹सौंदर्य₹ का प्रतीक है। लक्ष्मी पवित्रता और सौंदर्य अर्थात ₹ईमानदारी₹ और ₹सचाई₹ पर विराजमान हैं। उनका वाहन उल्लू है। उल्लू मूर्खता का प्रतीक है। *मूर्खतापूर्ण स्वभाव वाले या अवगुणी व्यक्तियों के लिए यह लक्ष्मी भार स्वरूप, दुःख रूप होती है।*यह दिग्दर्शन उनके चित्र में कराया गया है।

प्रेम पच्चीसा,,,(भाग 4)

राजेंद्र रंजन गायकवाड़
सेवानिवृत्त केंद्रीय जेल अधीक्षक
बिलासपुर, छत्तीसगढ़

रोहन, कवि, अपनी कविताओं के दम पर शहर में ख्याति प्राप्त कर चुका था। उसकी रचनाएँ लोगों के दिलों को छूती थीं और उसका सपना था कि वह एक दिन इतना बड़ा कवि बने कि उसकी कविताएँ हर घर में गूँजें। आज उसका सपना पूरा हो गया। साथ ही दीपा को भूल कर रोहन दिल माया पर आ गया था जो एक साधारण-सी लेकिन संवेदनशील घरेलू लड़की थी। माया को रोहन की कविताएँ बहुत पसंद थीं और वह अक्सर उसकी काव्य सभाओं में चुपके से आकर कोने में बैठकर सुनती थी। रोहन की आँखें हर महफ़िल माया को ही खोजतीं।

रोहन ने ठान लिया था कि वह माया से शादी करेगा लेकिन इसके लिए उसे अपने करियर / भविष्य को और ऊँचाइयों तक ले जाना होगा। उसने दिन-रात मेहनत की और रोहन का दूसरा कविता संग्रह #मुक्ताकाश प्रकाशित होने पर, राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन में महामहिम राज्यपाल के कर कमलों से राजधानी में विमोचित हुआ..,जिस से रोहन नाम समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर देशभर में फैल गया। एक दिन, शाम को रवींद्र भवन में भव्य काव्य सभा के बाद, उसने माया के सामने अपने दिल की बात रखी। माया, हमेशा से रोहन की सादगी और जुनून की कायल थी ने तत्काल हाँ कह दी। माया इसी पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। दोनों की शादी एक सादे लेकिन ख़ूबसूरत समारोह में हुई, जहाँ रोहन ने मित्रों को प्रीति भोज खिला कर माया की सादगी और ख़ूबसूरती को लेकर लिखी एक खास कविता पढ़ी, जिसे सभी को भावुक हुए और माया की आँखों में प्रेम जल छलछला आया।

उधर, दीपा की ज़िंदगी एक अलग मोड़ पर किंकर्तव्य-विमूढ़ खड़ी थी। रमेश के साथ उसकी शादी शुरू से ही तनावपूर्ण रही थी। रमेश का स्वभाव दीपा की स्वतंत्र आत्मा को रेशमी धागों से बाँधने वाला था। दीपा, एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी ने आख़िरकार फैसला किया कि वह इस दिखावटी रिश्ते को और नहीं निभा सकती। बिना अपने घर वालों और दोस्तों को बताएं , रमेश से तलाक ले लिया साथ ही दीपा ने ज़िन्दगी भर अकेले रहने का फ़ैसला किया। उसने एक छोटा-सा घर किराए पर लिया और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक बनकर ज़ीना शुरू किया। यूं तो, दीपा को लिखने का शौक था और वह कभी स्वतंत्र पत्रकार भी रही थी, अपनी भावनाओं और बीती ज़िंदगी के उतार - चढ़ाव को डायरी में उतारने लगी। धीरे-धीरे, उसकी डायरी के पन्ने एक कहानी का रूप लेने लगे। कहानी के हर पन्ने पर रोहन का हसीं चेहरा दीपा फ़ील करती थी।

एक दिन, रोहन की काव्य गोष्ठी में दीपा की मुलाक़ात माया से रोहन ने करवाई ,माया अब रोहन की पत्नी थी। धीरे -धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। माया ने दीपा को रोहन की काव्य गोष्ठी में आमंत्रित किया जहाँ दीपा की मुलाकात रोहन से दुबारा हुई। रोहन ने दीपा की डायरी पढ़ी और उसकी लेखन शैली से प्रभावित हुआ। उसने दीपा को प्रोत्साहित किया कि वह अपनी कहानियाँ प्रकाशित करे। दीपा जो पहले अपनी काबिलियत पर शक करती थी, अब आत्मविश्वास से भर उठी।

समय के साथ, दीपा ने अपनी पहली किताब #अनकहे रिश्ते प्रकाशित की जो एक आत्मकथात्मक उपन्यास था। उसकी किताब को लोगों ने खूब सराहा, और वह एक उभरती हुई लेखिका के रूप में जानी जाने लगी। दीपा ने अपनी आजादी को गले लगाया और फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी। उधर, रोहन और माया एक-दूसरे के सहारे अपनी कला को और निखारते रहे।

18 अगस्त: सुभाष चंद्र बोस पुण्यतिथि
गुमनामी से अमरत्व तक—नेताजी का अनंत सफर

"दिल्ली चलो!"—यह नारा मात्र एक उद्घोष नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय जनमानस में प्रज्वलित एक ज्वलंत क्रांति की चिंगारी था। उनकी पुण्यतिथि हमें उस अदम्य योद्धा को स्मरण करने का अवसर देती है, जिसने स्वतंत्रता को रक्त, बलिदान और अटूट संकल्प से जोड़ा। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा, जो न केवल औपनिवेशिक बेड़ियों से मुक्त हो, बल्कि अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के बल पर विश्व मंच पर सिर ऊँचा कर खड़ा हो। सुभाष चंद्र बोस का जीवन केवल इतिहास की पंक्तियों तक सीमित नहीं, बल्कि साहस, समता और आत्मनिर्भरता की वह प्रेरणा है, जो आज भी हमें दिशा दिखाती है। उनकी पुण्यतिथि पर हमें उनकी अनकही विरासत—उनके वैश्विक दृष्टिकोण, सामाजिक क्रांति की सोच और रहस्यमय अंत की गूँज को पुनर्जनन और सम्मान देना चाहिए।

सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। 1941 में जर्मनी में उन्होंने सैन्य सहायता मांगी और भारत के संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। जर्मन भाषा और यूरोपीय राजनीति की समझ के साथ उन्होंने प्रभावी संवाद किया। जर्मनी से समर्थन न मिलने पर भी उनका संकल्प अटल रहा। जापान में आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जनन दिया और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार स्थापित की, जो स्वतंत्र भारत का प्रशासनिक स्वप्न थी। जापान, जर्मनी, इटली से मान्यता प्राप्त इस सरकार में हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत सभी समुदायों को शामिल कर बोस ने एकता और समावेशिता का उदाहरण पेश किया।

सुभाष चंद्र बोस की सामाजिक दृष्टि स्वतंत्रता को सामाजिक समता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गौरव से जोड़ती थी। आज़ाद हिंद सरकार में लक्ष्मी सहगल को रानी झाँसी रेजिमेंट का नेतृत्व सौंपकर उन्होंने लैंगिक समानता का क्रांतिकारी कदम उठाया, जहाँ महिलाएँ पुरुष सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ीं। बोस का मानना था कि भारत की प्रगति जातिगत भेदभाव, सामाजिक रूढ़ियों और लैंगिक असमानता से मुक्ति के बिना असंभव है। उनकी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में वे एक आधुनिक भारत की कल्पना करते हैं, जो औद्योगिकीकरण, शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हो। यह प्रगतिशील सोच उस युग में, जब राजनीतिक स्वतंत्रता ही प्रमुख थी, एक सशक्त भारत का दूरदर्शी खाका थी।

सुभाष चंद्र बोस का बौद्धिक पक्ष उनकी नेतृत्व क्षमता जितना ही प्रभावशाली था। कैम्ब्रिज की शिक्षा ने उन्हें पश्चिमी दर्शन और राजनीति से जोड़ा, पर वे भारतीय संस्कृति और दर्शन से गहरे जुड़े रहे। स्वामी विवेकानंद और रवींद्रनाथ टैगोर का प्रभाव उनके लेखन और भाषणों में दिखता था। "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा" जैसे आह्वान ने आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से युवाओं में आत्मविश्वास और क्रांति की ज्वाला जलाई। जनमानस को प्रेरित करने और विचारों के स्तर पर क्रांति रचने की उनकी क्षमता उन्हें एक अप्रतिम नेता बनाती थी।

सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि का रहस्य उनकी मृत्यु के इर्द-गिर्द अनुत्तरित प्रश्नों से जुड़ा है। आधिकारिक दस्तावेज़ दावा करते हैं कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, पर मुखर्जी आयोग ने इसे खारिज कर संकेत दिए कि बोस शायद सोवियत संघ में जीवित रहे या भारत में "गुमनामी बाबा" के रूप में 1985 तक रहे। यह रहस्य उनकी मृत्यु से परे स्वतंत्रता संग्राम की अधूरी गाथा को दर्शाता है, जो बोस को एक अमर किंवदंती बनाता है, जो हमें उनके सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है।

सुभाष चंद्र बोस की संगठनात्मक अनुशासन की भावना उनकी विरासत का एक अनमोल रत्न है। आज़ाद हिंद फौज केवल एक सैन्य संगठन नहीं थी; यह एक ऐसी प्रयोगशाला थी, जहाँ सैनिकों को युद्ध कौशल के साथ-साथ नैतिकता, अनुशासन और अटूट देशभक्ति की शिक्षा दी जाती थी। बोस का दृढ़ विश्वास था कि कोई आंदोलन तभी विजयी हो सकता है, जब वह सैन्य-जैसी अनुशासनबद्धता और एकता से

संचालित हो। उनकी फौज में विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, जो उस युग के भारत में सामाजिक एकता का एक प्रेरक प्रतीक था। "कर्म ही पूजा है" का उनका मंत्र हर सैनिक के हृदय में गूँजता था, जो उनकी नेतृत्व शक्ति का जीवंत प्रमाण था।

सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर हमें उनके स्वप्नों—आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समता और सांस्कृतिक गौरव से युक्त भारत—के प्रति आत्ममंथन करना होगा। उनकी दूरदर्शी सोच, औद्योगिकीकरण, शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आज भी प्रासंगिक है। भारत आज आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव और शिक्षा की कमी से जूझ रहा है। बोस का जीवन सिखाता है कि इनका समाधान क्रांतिकारी दृष्टिकोण, अटूट संकल्प और सामूहिक इच्छाशक्ति से ही संभव है। उनकी पुण्यतिथि हमें उनके बलिदान को याद कर उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेने का अवसर देती है।

सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि महज एक औपचारिक स्मरण नहीं, बल्कि एक प्रज्वलित संकल्प है—उनके अधूरे सपनों को साकार करने और उनकी अमर गाथा को जीवंत रखने का। उनका जीवन हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता कोई स्थिर उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है, जिसमें प्रत्येक पीढ़ी को अपने युग की चुनौतियों से टकराना पड़ता है। "जय हिंद" का उनका नारा केवल एक उद्घोष नहीं, बल्कि एक प्रेरक आह्वान है—साहस, समर्पण और आत्मनिर्भरता के साथ उस भारत को रचने का, जिसके लिए बोस ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनकी पुण्यतिथि हमें यह स्मरण कराती है कि सच्ची श्रद्धांजलि उनके बलिदान को केवल याद करना नहीं, बल्कि उनके दिखाए पथ पर अडिग होकर एक सशक्त, समृद्ध और समतामूलक भारत का निर्माण करना है। यह दिन हमें न केवल उनकी विरासत को सम्मान देने, बल्कि उनके आदर्शों को जीकर एक नए भारत के स्वप्न को साकार करने का प्रण लेने का अवसर देता है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

वीरेंद्र सचदेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली की जानता को 11,000 करोड़ की दो हाई स्पीड कॉरिडोर देने के लिए आभार जताया

मुख्य संवाददाता/सुषमा रानी

नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली की जानता को 11,000 करोड़ की दो हाई स्पीड कॉरिडोर देने के लिए आभार जताया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा की इस हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण केन्द्र सरकार ने तत्कालीन ₹आपर सरकार के समय शुरू किया था और आज यह लोकार्पित हुआ है जो एक बार फिर दर्शाता है की प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा दिल्ली के विकास की चिंता की है

द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड जो शिव मूर्ति से दिल्ली-हरियाणा सीमा तक और अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) का लोकार्पण किए जाने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार जताया है।

इस ऐतिहासिक अवसर का गवाह दिल्ली के लाखों लोग हुए जिन्होंने एक सुर में बोला - धन्यवाद पीएम मोदी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछले 10 सालों से जो विकास के अधूरे काम दिल्ली में रुके हुए थे अब वह भाजपा की डबल इंजन की सरकार पूरा करने का काम कर रही है। दिल्ली को विकास की नई रफ्तार देने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।

उन्होंने कहा कि राजधानी में भीड़भाड़ कम करने के लिए सरकार की दोनों योजना के तहत विकसित किया गया है। इन दोनों हाई स्पीड कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार, यात्रा समय को घटाना और दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 10.1 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड लगभग 5,360 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। 3.6 किलोमीटर का लंबा एक शानदार टनल भी दिल्ली वालो को भेंट किया गया है। यह खंड यशोभूमि, डीएमआरसी की ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

सचदेवा ने कहा कि अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) का अलीपुर से दीछाऊं कलां तक का हिस्सा, बहादुरगढ़ और सोनीपत से नए संपर्कों के साथ, लगभग 5,580 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। यह दिल्ली की इनर और आउटर रिंग रोड्स तथा मुकर्बा चौक, धौला कुआं और एनएच-09 जैसे व्यस्त स्थानों पर ट्रैफिक को कम करने में मदद करेगा।

सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को विकास की नई रफ्तार देने के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है और आम आदमी पार्टी के 10 सालों के निष्क्रिय शासन का अंत करके दिल्लीवालों ने विकास को चुना है और उसी सीरिज में अब दिल्ली 8 लेन के द्वारका एक्सप्रेस वे के बाद जाम मुक्त होगी।

वोट चोरी के लग रहे आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान

मुख्य संवाददाता/सुषमा रानी

नई दिल्ली। वोट चोरी के लग रहें आरोप को लेकर रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने बिना नाम लिए स्पष्ट कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए हलफनामा देना होगा, अन्यथा देश से माफी मांगनी होगी।

आयोग ने कहा कि हमारे लिए न कोई पक्ष है, न ही विपक्ष है, बल्कि सभी समकक्ष हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) ने कहा कि किसी भी शिकायत के लिए आयोग के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल सरासर गलत है, ऐसे मामलों में कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वोटर्स के फोटो, नाम और पहचान सार्वजनिक रूप से दिखाई गई, जो कि पूरी तरह से गलत है।

नेशनल मीडिया सेंटर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदाता बनना चाहिए और मतदान भी करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग (Election Commission) में पंजीकरण के माध्यम से होता है। फिर चुनाव आयोग (Election Commission) समान राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग (Election Commission) के लिए न तो कोई विपक्ष है और न ही कोई पक्ष। सभी समान हैं। चाहे कोई किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, चुनाव

आयोग (Election Commission) अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) ने कहा कि पिछले दो दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग (Election Commission) ने बिहार से एक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की शुरुआत की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाताओं, बूथ स्तर के अधिकारियों और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLA ने मिलकर एक मसौदा सूची तैयार की है।

चुनाव आयोग ऐसे झूठे आरोपों से नहीं डरता

चुनाव आयोग ऐसे झूठे आरोपों से डरता नहीं है। चुनाव आयोग बिना कसिी मतभेद चट्टान की तरह खड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, वोट चोरी जैसे गलत शब्द का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो ये भारत के संविधान का अपमान है। मशीन रिडेबल मतदाता सूची न साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये मतदाता के निजता का उल्लंघन है. लेकिन फरि भी कुछ दलों की ओर से ये कयिा गया।

स्वदेशी में बनी वस्तुओं को खरीदने व बेचने को लेकर फेस्टा चलाएगा मुहिम - परमजीत सिंह पम्मा

मुख्य संवाददाता

दिल्ली। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार कहा है कि भारतीय हैं तो भारत में बना सामान ही खरीदें। दीवाली पर भी वही सामान खरीदें, जो भारतीयों ने भारत में बनाया है। व्यापारी भी विदेशी सामान छोड़कर लोकल सामान बेचें इसको लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन (फेस्टा) के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा व अध्यक्ष राकेश यादव ने प्रधानमंत्री जी इस मुहिम का समर्थन देते हुए कहा फेडरेशन सदर बाजार में इस मुहिम को चलाएगी। क्योंकि जिस तरह से विदेशी ताकतें भारत को काम पर लगाने में लगी हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए व्यापारियों का सहयोग जरूरी है और अपने देश का सामान बेचने और खरीदने में देश की ताकत और मजबूत होगी।

पम्मा व राकेश यादव ने कहा जिस प्रकार अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका में भारत में बने हुए सामान न बेचने की साजिश रच रहा है। इसका भारत के व्यापारिक विदेशी माल ना खरीद कर और न बचकर मुंह तोड़ जवाब देंगे क्योंकि हमारे देश की आबादी इतनी है। हमारी इंडस्ट्री के बने सामान उनकी पूर्ति करने में ही खपत हो जाएंगे और हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पम्मा व राकेश यादव ने बताया पहले खिलौने, मूर्ति व लाइट समेत अन्य वस्तु विदेश से आते थे मगर अब भारत में निर्माण हो रहे हैं। जोकि बहुत ही अच्छे और तरीके से बना रहे हैं। विदेशी सामान पूरी तरह से मुकाबला कर रहा है।

पम्मा व राकेश ने कहा जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया है के दिवाली पर जीएसटी पर भी कुछ राहत मिलेगी। उसको लेकर भी व्यापारियों में काफी उत्साह है और अगर जीएसटी में कुछ कमी आती है तो उसे और भी विदेशी बनी वस्तुओं के दामों में मुकाबला करने में एक अच्छा कदम होगा।

स्वतंत्रता दिवस पर जवाहर पार्क में डॉक्टर मिथिलेश कुमार द्वारा लगातार 15वीं बार राष्ट्रीय ध्वजारोहण

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। जवाहर पार्क ई ब्लॉक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर मिथिलेश कुमार द्वारा अपनी पूरी टीम एवं स्थानीय लोगों के साथ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर लगातार 15वीं बार राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया। संगठन के महासचिव बृजभूषण मिश्रा द्वारा आय व्यय का लखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया तथा पिछले लेखा-जोखा की संपुष्टि की गई। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा में निर्वाचित सदस्यों एवं अन्य सदस्य गणों के हस्ताक्षर एवं सहमति से कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। आज की आम सभा में सर्दिय नवरात्रि के भव्य एवं दिव्य आयोजन तथा भंडारे पर भी गंभीरता से विचार कर इसको अंतिम रूप दिया गया। इसमें विशेष बात यह रखी गई कि स्थानीय लोग सपरिवार इस भंडारे में ही भोजन करेंगे। इस अवसर पर उप प्रधान महेश उपाध्याय, नीरज शर्मा, नवीन ठाकुर, जयराम शर्मा, भोला शर्मा, सोहन दास, मोहर सिंह, आकाश यादव, इंदर सिंह कैन, राकेश त्यागी, कृष्णा बिंदल, चरण सिंह, इंद्रजीत बारी, कुलदीप सिंह, राज किरण ठाकुर, श्याम तिवारी आरडब्ल्यूए महिला मंडल सदस्यों में माया देवी, नेहा रानी, तुलसी रानी, कलावती दुबे, धर्मावती प्रजापति, रेखा राजपूत, शबनम शर्मा, अंजना ठाकुर, आदि उपस्थित रही। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा भी निकला गया जिसका समापन एडवोकेट इशिता गौतम के आवासीय कार्यालय पर संपन्न हुआ। आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष डॉ मिथिलेश कुमार एवं प्रमोद कुमार सिंह द्वारा एडवोकेट इशिता गौतम के कार्यालय उद्घाटन अवसर पर उन्हें गुलदस्ता प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। प्रधान डॉक्टर मिथिलेश कुमार के सुपुत्र अस्मित मिथिलेश एवं अमृत मिथिलेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार, मेडल एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। अस्मित मिथिलेश एवं अमृत मिथिलेश द्वारा इंटरनेशनल टॉपर sof ओलंपियाड का खिताब जीतने पर उन्हें बधाई दी गई। महासचिव बृजभूषण मिश्रा एवं रितु मिश्रा की पुत्री श्रेया मिश्रा का अंबेडकर विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस में अर्थशास्त्र ऑनर्स के लिए चयनित होने पर उन्हें भी पुरस्कृत किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जाने को तैयार नहीं दिल्ली के लोग : सौरभ भारद्वाज

मुख्य संवाददाता/सुषमा रानी

नई दिल्ली। पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली है और चूंकि 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो भाजपा ने एक भव्य रैली का आयोजन करने का प्लान तैयार किया। लगभग 1 लाख लोग रैली में जुटाने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ जो व्यवहार किया, दिल्ली की जनता की जो हालत बना दी है, उससे दिल्ली की जनता इतनी नाराज है, कि लोग प्रधानमंत्री की रैली में नहीं जाना चाहते। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यही कारण है, कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को डंडे के जोर पर रैली में ले जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह बड़े ही शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी, मलेरिया विभाग के कर्मचारी, लाइसेंस विभाग के कर्मचारी और नगर निगम स्कूल के अध्यापकों को जबरदस्ती डंडे के जोर पर रैली में ले जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की इस प्रकार की हरकतों को देखते हुए किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठाना लाजमी है, कि आखिर 6 महीने में दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाने को तैयार नहीं है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल जन्माष्टमी थी। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात को 12:00 बजे के बाद मंदिर जाकर दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, घर आते हैं। इन सब क्रियाओं में लोगों को सोने में लगभग 2:00 बज

जाते हैं। जन्माष्टमी के अगले रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग नवमी की पूजा करते हैं। यह बड़े ही शर्म की बात है, कि जिन कर्मचारियों ने कल दिन में अपना काम किया, रात में वह सभी लोग पूजा पाठ और मंदिरों के लिए देर रात तक व्यस्त रहे, आज छुट्टी वाले दिन जब कुछ लोगों को नवमी की पूजा करनी थी, अपने घरों में आराम करना था, उन्हें भाजपा की नगर निगम की ओर से आदेश जारी किया जाता है, कि कल सुबह 7:00 बजे निम्न स्थान पर पहुंचे आप सब की हाजिरी ली जाएगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल छुट्टी के दिन सभी जोन में डिप्टी कमिश्नर अपने अपने जोन के कार्यालय में बैठे हुए थे और अलग-अलग विभाग के कर्मचारी के लिए आदेश जारी किए जा रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ जुटाना के लिए काम चल रहा था। इस संबंध में सौरभ भारद्वाज ने नगर निगम के शिक्षा विभाग के सेंट्रल जोन के लिए डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किया गया एक आदेश पत्रकारों के समक्ष रखते हुए बताया कि इस आदेश में साफ तौर पर लिखा है, कि नगर निगम के अध्यापकों को सुबह 7:00 बजे बताए गए स्थान पर पहुंचना है और 7:30 बजे वहां से बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए रवाना होगी। साथ ही धमकी दी गई है, कि इस रैली में डिप्टी कमिश्नर के आदेश अनुसार चुने गए सभी अध्यापकों को आना अनिवार्य है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के राज में एक तानाशाही चल रही है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं जाना चाहते? उन्होंने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली की जनता भाजपा के साथ नहीं है। भाजपा ने दिल्ली में जो चुनाव जीता वह छल से जीता। लोगों के वोट काटे गए, फर्जी वोट बनवाए गए, पैसा बांटा गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता हथियाई। उन्होंने कहा कि धोखे से सत्ता हथियाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ जो किया, सत्ता में आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई जिससे मध्यम वर्ग आज भाजपा से नाराज है। झुग्गी बस्तियों पर, लोगों के रोजगारों पर बुलडोजर चलाकर लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया उनकी रोजी रोटी छीन ली गई, जिससे गरीब वर्ग आज भाजपा से नाराज है। पिछले कुछ दिनों में हुई बरसात के कारण अलग-अलग जगह पर भाजपा की लापरवाही से 30 लोगों की मृत्यु हो गई। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज स्थिति यह है के लोग आवारा कुत्तों की सुरक्षा के लिए तो इकट्ठा होने को तैयार हैं, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाने को तैयार नहीं है।

उन्होंने बताया कि केवल सरकारी कर्मचारियों के साथ ही नहीं बल्कि लाइसेंसिंग विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली में रेडी पटरी लगाने वाले लोगों को भी धमकी दी और कहा कि आप सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाना है, अन्यथा आप सबको रेडी पटरी नहीं लगने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की यह हालत हो गई है, कि गरीब आदमी भाजपा की रैली में जाने को तैयार नहीं है और अमीर आदमी टीवी पर भाजपा को देखने को तैयार नहीं है।

दिल्ली सरकार जल्द से जल्द करें समितियों में सलाहकार का गठन: भास्कर

नई दिल्ली: जहांगीरपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एमएल भास्कर ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार को बने लगभग 6 महिने बीत चुके है, परन्तु अभी तक सरकार विभिन्न कमेटियों जैसे थाना, स्कूल, हॉस्पीटल आदि कमेटियों का गठन नहीं कर सकी है। उन्होंने आगे बताया कि शासन-प्रशासन के सुचारु संचालन और नीतिगत निर्णयों में विशेषज्ञ राय को शामिल करना जरूरी होता है। सरकार के लगभग 6 महिने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक किसी भी समिति में औपचारिक रूप से अस्तित्व में नहीं आना सरकार की विफलता का सबूत है। एमएल भास्कर ने आरोप लगाते हुए कहा कि समितियों के गठन नहीं हो पाने से इन विभागों की नीतियों में पारदर्शिता और जनभागीदारी की कमी बनी हुई है। श्री भास्कर ने कहा कि सलाहकार समितियों के गठन से सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करती है, जिससे निम्न विभागें की गुणवता प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सलाहकार समितियों का गठन किया जाये।

जनता द्वारा अपना दर्द सड़कों पर रोष प्रदर्शन करने पर निगम आयुक्त एवं स्थानीय नेता जिम्मेदार होंगे तमाम पीड़ित नागरिकों के द्वारा

परिवहन विशेष न्यूज

ओल्ड डी सी रोड सोनीपत में आर्य समाज मंदिर एवं दुर्गा मंदिर के बीच पिछले कई महीनों से पानी के जल भराव के कारण सड़कों के गड्ढे की वजह से प्रति दिन दो पहिया एवं तीन पहिया वाहनों का नुकसान तथा पलटने के कारण हजारों लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारियों एवं नेताओं ने बारिश का हवाला देते हुए आम नागरिकों की समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता न समझते हुए उनके हालात पर ही छोड़ दिया है और इसके अलावा शनि मंदिर अंडर पास में बारिश के बाद जो कूड़ा एवं कचरा तथा मलबा सड़कों के किनारे तथा जालियों के आस पास पड़ा रहता है इन तमाम रूकावटों को भी तुरंत प्रभाव से हटवाना आवश्यक होता है ताकि भविष्य में जल भराव में रोकथाम नहीं हो अगर बार बार गिड़गिड़ाने के बावजूद भी किसी प्रकार की नागरिकों को सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है तो मजबूरी में जनता अपना दर्द सड़कों पर किसी भी तरह से रोष प्रदर्शन करने पर निगम आयुक्त एवं स्थानीय नेता जिम्मेदार होंगे तमाम पीड़ित नागरिकों के द्वारा।

एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर तिरंगा लगाया

परिवहन विशेष न्यूज

एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू सदस्य मनीष साहू के नेतृत्व में संस्था के माध्यम से 79 वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत संस्था पदाधिकारियों ने हल्द्वानी में घर घर जाकर तिरंगा लगाया

इस दौरान एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू सदस्य दीपक कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि 1947 में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाकर प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण प्राप्त हुआ है क्योंकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश की स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिकता को दर्शाता है और यह भारत देश की एकता अखंडता प्रगति उन्नति समृद्धि खुशहाली का सूचक है इसलिए हम सभी भारतीयों का यह परम कर्तव्य है कि भारत माता भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान के प्रति त्याग तपस्या समर्पण भाव के साथ कर्तव्य पथ पर सतत डटे रहने के लिए संकल्पित होकर यह संकल्प लें की हम सभी भारतीय एकता के एक सूत्र में बंधकर भारत देश को विश्वगुरु बनाने के लिए हम आस्था निष्ठा दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ हमेशा धर्महित समाजहित भारतहित में कार्य करते रहेंगे इसीलिए शहीदों ने अपने अद्वितीय साहस और पराक्रम से भारत देश की गौरव गाथा को लिखा है उनका अद्भुत शौर्य हमारे स्वर्णिम इतिहास की एक मुकुटमणि है जो मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान के लिए कैसी परिश्रम की पराकाष्ठा हो ये शहीदों का सम्पूर्ण जीवन हम सभी भारतीयों को दृढ़ संकल्प शक्ति साहस के सुपथ पर चलने और भारत माता कि सेवा करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है जिससे हम भारतीय अपनी देशभक्ति को और विराट रूप से प्रखर कर भारत देश को विश्व के शिखर पर कीर्तिमान स्थापित करने में अपना अहम योगदान देकर भारत देश को

विश्वगुरु बनाने में सहयोग करें जिससे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा संपूर्ण ब्रह्मांड में बड़ी शान के साथ हमेशा लहराता रहे

इस दौरान तिरंगा लगने में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू सूरज मिस्त्री मनीष साहू निखिल कुमार दीपक कुमार सुशील राय अमन कुमार सूरज कुम्हार विजय डंगवाल मुकेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे।

मनीषा हत्याकांड : हरियाणा की कानून-व्यवस्था पर सवाल

मनीषा की हत्या ने हरियाणा की पुलिस और शासन व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, चित्रण देर से लेना और परिजनों की गुहार को नज़रअंदाज़ करना – ये सब पुलिस की लापरवाही के प्रमाण हैं। परिवार का शव न लेने का फैसला एक प्रतीक है कि अब जनता केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होगी। सरकार को यह समझना होगा कि महज़ तबादले और निलंबन से हालात नहीं सुधरेंगे। जब तक पुलिस जवाबदेह नहीं होगी और समाज में महिलाओं के प्रति नज़रिये में बदलाव नहीं आएगा, तब तक ऐसी दर्दनाक घटनाएँ होती रहेंगी।

- डॉ सत्यवान सौरभ

भिवानी ज़िले की उन्नीस वर्षीय शिक्षिका मनीषा की हत्या ने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला केवल एक बेटी की असमय मौत भर नहीं है, बल्कि हरियाणा की पुलिस व्यवस्था, समाज और शासन तंत्र पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न भी है। सवाल यह है कि आखिर क्यों हर बार बेटियों की सुरक्षा तब चर्चा का विषय बनती है जब कोई दर्दनाक घटना घट जाती है? क्यों पुलिस की प्राथमिक प्रतिक्रिया संवेदनशील और सक्रिय होने के बजाय उपेक्षा और पूर्वाग्रह से भरी रहती है?

मनीषा ग्यारह अगस्त को नर्सिंग कॉलेज से लौटते समय लापता हो गई। परिजनों ने उसी दिन पुलिस को शिकायत दी। मगर पुलिस का रवैया बेहद उपेक्षापूर्ण था। पिता को यह कहकर टाल दिया गया कि "लड़की भाग गई होगी, खुद लौट आएगी।" यह बयान केवल पुलिस की संवेदनहीनता नहीं दर्शाता बल्कि यह भी बताता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ अब भी पुरानी जड़ मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई हैं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट अगले दिन दर्ज की गई और कॉलेज का बंद परिपथ यंत्र का चित्रण भी तेरह अगस्त को जुटाया गया। यानी तीन दिन तक समय बर्बाद हुआ। इस दौरान मनीषा का गला रेतकर हत्या कर दी गई और शव को जलाने की कोशिश की गई। अगर पुलिस ने तुरंत गंभीरता दिखाई होती, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। यह मामला हर उस परिवार के डर को सच साबित करता है जो अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजते समय दिल पर पत्थर रखते हैं।

मनीषा के परिवार ने जब शव देखा तो उनका दुःख आक्रोश में बदल गया। उन्होंने शव लेने और अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यह प्रतिरोध केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज की पीड़ा है।

भिवानी नागरिक अस्पताल में लगातार धरना चला। गाँव-गाँव से लोग समर्थन में पहुँचे। यह संघर्ष हमें याद दिलाता है कि न्याय के लिए जनता को बार-बार सड़क पर उतरना पड़ता है। आखिर यह कैसा लोकतंत्र है जहाँ नागरिक को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए शव लेकर धरने पर बैठना पड़े?

चरखी दादरी, भिवानी, बाढड़ा, भांड़वा और लोहारू सहित कई कस्बों में बाज़ार बंद हुए। सड़कों पर जाम लगा। मोमबत्ती मार्च निकाले गए। यह जनता का सीधा संदेश था कि

अब और सहन नहीं होगा। जब भी व्यवस्था अपने कर्तव्य से चूकती है, जनता का आक्रोश ही उसे आईना दिखाता है। लोगों की माँग थी कि दोषियों को फाँसी दी जाए। उनकी नाराजगी केवल अपराधियों से नहीं थी, बल्कि उस तंत्र से भी थी जिसने समय रहते कार्रवाई नहीं की।

बढ़ते जनाक्रोश ने मुख्यमंत्री को कदम उठाने पर मजबूर किया। उन्होंने भिवानी पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया और पाँच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। सवाल यह है कि क्या सिर्फ़ निलंबन और तबादले से बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? क्या पुलिस सुधार का मतलब केवल नाम बदलना और कुर्सी बदलना भर है? यह कदम राजनीतिक दबाव में उठाए गए अस्थायी उपाय भर लगते हैं।

विपक्ष ने इस मामले को तुरंत मुद्दा बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उनका बयान गलत नहीं है। जब लोग पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तब यह साफ है कि व्यवस्था की जड़ें खोखली हो चुकी हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि विपक्षी दल केवल बयानबाज़ी तक सीमित रहते हैं। सत्ता में रहते हुए उन्होंने भी पुलिस सुधार और महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। इसलिए दोष केवल वर्तमान सरकार का नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र का है, जिसने कभी इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी।

हर हत्या के बाद हम मोमबत्तियाँ जलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं और कड़ी सज़ा की माँग करते हैं। लेकिन क्या इसके बाद हमारे समाज का रवैया बदलता है? बेटियों को घर से बाहर निकलते समय शक की निगाह से देखना, उनकी स्वतंत्रता पर बंदिश लगाना और पुलिस का 'भाग गई होगी' वाला दृष्टिकोण — ये सब हमारी सामूहिक मानसिकता की गवाही देते हैं। हमें यह समझना होगा कि अपराधियों का हौसला तभी टूटेगा जब समाज बेटियों को बराबरी का अधिकार और सुरक्षा का वातावरण देगा।

सुधार की राह साफ है। हर शिकायत को तुरंत दर्ज करना अनिवार्य होना चाहिए। गुमशुदगी के मामलों में "भाग जाने" वाली सोच को खत्म करना होगा। केवल निलंबन काफी नहीं है। दोषी अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज हो और सख़्त सज़ा मिले। कॉलेज, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी व्यवस्था और पुलिस गश्त मजबूत होनी चाहिए। महिला अपराधों की सुनवाई शीघ्र हो और हर मामला छह महीने के भीतर निपटाया जाए। घर-परिवार से लेकर पंचायत और समाज तक यह संदेश जाए कि बेटियों की सुरक्षा केवल सरकार नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

मनीषा हत्याकांड ने यह साबित कर दिया है कि हरियाणा में कानून-व्यवस्था कितनी खोखली है। यह मामला केवल एक बेटी का नहीं, बल्कि हर घर की चिंता का विषय है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो कल और कितनी मनीषाएँ इस व्यवस्था की भेंट चढ़ेंगी, कहना मुश्किल है।

"मनीषा की अरदास"

मत रो माँ, अब मत रो,
तेरी बेटी की आवाज़ हम सब हैं,
न्याय की राह पर चल पड़े,
अब जाग उठा हर जन-जन है ।

गूँजे धरती, गगन गवाह,
अन्याय के विरुद्ध उठे निगाह।
'भाग गई होगी' कहना भूल,
अब टूट चुका हर झूठा फूल।

मनीषा तेरी कसम हमें,
लड़ेंगे जब तक साँस है।
न्याय की ज्वाला जलती रहे,
हर दिल में अब विश्वास है।

मोमबत्तियों का यह सागर,
बन जाए अग्नि का दरिया,
क़ातिलों को सज़ा मिले,
नारी फिर हो न दु:खिया।

मत रो माँ, अब मत रो,
तेरी बेटी की आवाज़ हम सब हैं,
न्याय की राह पर चल पड़े,
अब जाग उठा हर जन-जन है ।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

हत्यारोपी हिस्ट्रीशीटर बदमाश पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल से फरार मुठभेड़ में पैर में लगी थी गोली जिला अस्पताल में चल रहा था इलाज। अब पुलिस को चकमा देकर हुआ फुर्र पुलिस विभाग में मचा हड़कंप।

राष्ट्रीय युगल दिवस आज

18 अगस्त, को दुनिया राष्ट्रीय युगल दिवस मना रही है। यह दिन हर साल युगलों द्वारा एक-दूसरे के प्यार और एकजुटता को संजोने के लिए मनाया जाता है। यह युगलों के बीच के अनोखे बंधन को दर्शाता है, जो यादें और जीवन के अनमोल पल रचते हैं, और साथ मिलकर खुशियाँ और चुनौतियाँ साझा करते हैं। पूरे देश में प्यार में डूबे दो लोग राष्ट्रीय युगल दिवस को खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। यह दिन दोनों पार्टनर्स को एक-दूसरे के प्रति अपने प्यार का इज़हार करने और उन्हें ख़ास महसूस कराने का एक ख़ास मौक़ा देता है।

राष्ट्रीय युगल दिवस: इतिहास

राष्ट्रीय युगल दिवस पहली बार २०१० में मनाया गया था जब एक अमेरिकी कंपनी ने अपने उत्पाद के प्रचार के लिए यह चलन शुरू किया था। हालाँकि, यह चलन लोकप्रिय होता गया और अंततः रिश्तों के लक्ष्यों के उत्सव के रूप में उभरा। यह आयोजन अब एक वैश्विक आयोजन बन गया है जिसे दुनिया भर के जोड़े पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं।

राष्ट्रीय युगल दिवस: महत्व

राष्ट्रीय युगल दिवस एक विशेष अवसर है जो रोमांटिक रिश्तों में बंधे जोड़ों को सम्मानित करता है। यह दिन ऐसे जोड़ों को सम्मानित करने और उन्हें एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने, अपनी भावनाओं को साझा करने, अपने भावनात्मक बंधन को मज़बूत करने और अपने स्नेह का इज़हार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। रिश्ते में, अक्सर जोड़े एक ऐसे दौर से गुज़रते हैं जब उनके बीच का प्यार कम हो जाता है, और वे एक-दूसरे को दरकिनार करके किसी और परिवार के सदस्य पर ध्यान देने लगते हैं। हालाँकि, रिश्ते में एक-दूसरे को समझना और प्यार व परवाह की भावनाएँ साझा करना ज़रूरी है ताकि रिश्ते में चिंगारी बनी रहे।

जोड़े इस विशेष दिन को कैसे मनाते हैं?

यह कपल्स के लिए अपने रोमांटिक रिश्ते को मज़बूत करने का एक ख़ास दिन है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए, वे कई तरह की गतिविधियाँ आयोजित करते हैं, जैसे वे एक फिल्म रात के लिए जाते हैं।

*** अपना प्यार दिखाने के लिए एक-दूसरे को उपहारों का आदान-प्रदान करें**

* एक-दूसरे को पत्र लिखकर अपनी भावनाएँ व्यक्त करें

* घर पर एक साथ भोजन तैयार करें,

* यादें बनाने और कई अन्य चीजें करने के लिए छुट्टियों पर जाएं

मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है!-जाना पड़ सकता है जेल!

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर दुनियां में भारत ही एक ऐसा देश है जहां हजारों समाज, लाखों जातियां, उपजातियां धर्म व आध्यात्मिक आस्था की जड़ कहा जाता रहा है, जिसकी गिनती विदेशो में भारतीय खूबसूरती की विशेषताओं में से एक है। कई सैलानी इस अनोखी व्यवस्था को देखनें ही भारत यात्रा पर आते हैं और कहते हैं काबिल-ए-तारीफ़! इसी कारण ही भारत धर्मनिरपेक्ष देश की ताक़त से प्रसिद्ध है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र, मानता हूं के भारतीय रीति रिवाज को हर समाज स्तर पर अलग अलग रूप से लागू किया जाता रहा है, परंतु बहुत सी ऋतियां और रिवाज ऐसे हैं जो करीब करीब हर समाज जाति में कॉमन है, उन्हें में से एक है, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उस परिवार में 13 दिवसीय शोक मनाया जाता है तथा अंतिम दिन को, 13 वीं या 12 वीं दिन के रूप में अंतिम दिन मृत्यु भोज दिया जाता है, जिसे समाज स्तर व पारिवारिक व रिश्तेदारों के लोग शामिल होते हैं। परंतु समय के बदलते परिपेक्ष में आजकल समय अभाव के कारण समाज में अपने-अपने समय अनुसार मृत्यु भोज दिया जाता है, तो अनेक समाजों में यह मृत्यु भोज केवल पारिवारिक व रिश्तेदारी तक सीमित कर दिया गया है, जो कि इस प्रकार के नियम समझो कि पंचायत द्वारा ही बनाए गए हैं, जो मेरा मानना है कि काफी हद तक उचित भी हैं।हमारी राइस सिटी गोंदिया नगरी के कुछ समाजों के प्रबुद्ध नागरिकों से इस मृत्यु भोज के विषय पर मेरी लंबी चर्चा हुई तो, उन्होंने कहा हमारे समाज में मृत्यु भोज प्रतिबंधित है परंतु समाज के लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों तक सीमित रूप से मृत्यु भोज की रस्म करते रहते हैं। यह चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आज 16 अगस्त 2025 को एक महिला ने डिस्पोजल शॉप पर बताया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, वह उसकी 13 वीं में मृत्यु भोज कर रहे हैं। पूरे 13 दिवसीय शोक में एक लाख रुपए से अधिक खर्च आ गया है, व मृत्यु भोज पर भी करीब 40-50 हज़ार रुपए खर्च होगा। उन्होंने कहा कि वह यह मृत्यु भोज नहीं करना चाहती है परंतु कुछ समाज के लोगों ने कहा इससे समाज वाले उंगली उठाएंगे, बदनाम करेंगे, व सामाजिक प्रतिष्ठा कम होगी! इसलिए मैं यह सब कर रही हूं। बस! इसलिए मैंने आज इस विषय पर आर्टिकल लिखने की सोचा और मैंने फिर इस पर रिसर्च शुरू की तो, मुझे राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 मिला, जिसके तहत मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है, जेल जाना पड़ सकता है। उसमें 1 साल की सजा वह 1000 रुपए जुर्माना की सजा है।दुसरा 13 दिसंबर 2023 तारीख़ की राजस्थान पुलिस की एक सोशल मीडिया पर पोस्ट मिली जिसमें लिखा था, मृत्यु भोज करने और उसमें शामिल होना कानूनं दंडनीय अपराध है। मानवीय दृष्टिकोण से भी यह आयोजन अनुचित है, इसलिए आओ मिलकर इस कुरीति को समाज के से दूर करें, इसका विरोध करे।चूंकि राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत मृत्यु भोज कानून दंडनीय अपराध है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे पारिवारिक सदस्य की मृत्यु पर 13 दिवसीय शौक पर मृत्यु भोज को कुरीति/रीति/धार्मिक संस्कार पर बस छिड़ी। राष्ट्रीय स्तरपर इसका समाधान होना जरूरी है।

साथियों बात अगर हम मृत्यु भोज की करें तो, हिंदू परिवारों में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए परिजन अंतिम संस्कार के बाद विधि विधान से तेरह दिन पर तेरहवीं के रूप में मृत्यु भोज रखते हैं, मगर राजस्थान पुलिस का फरमान देख लगता है कि यह लोगों का अधिकार नहीं बल्कि अपराध है। राजस्थान पुलिस ने 13 दिसंबर की सुबह सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया था - मृत्यु भोज करना और उसमें शामिल होना कानूनन दंडनीय है। मानवीय दृष्टिकोण से भी यह आयोजन अनुचित है, तो क्या किसी को भोज दे ही नहीं?असल में मृत्यु भोज ऐक्ट आज का नहीं है, यह 1960 से है। इसमें साफ लिखा है कि मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है। सजा के रूप में एक साल तक का या एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें साफ है कि धार्मिक संस्कार के तहत रखे गए भोज में सौ से ज्यादा लोगों की संख्या नहीं होनीचाहिए। एक्ट बने इतने साल बीत गए मगर हकीकत यह है कि लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। राजस्थान पुलिस के ट्वीट पर भी कई लोगों की प्रतिक्रिया थी कि क्या ऐसा भी कोईकानून है। ऐसा कहने वाले भी कम नहीं थे कि यह उनका निजी विषय है। एक ने एक्स पर लिखा-ऐसे हिंदू विरोधी क़ानून बंद करें।यह हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं।इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती। हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से ही करता है। तो कुछ लोगों ने इसके समर्थन में भी पोस्ट किया। एक ने लिखा-हमारे यूपी में भी ऐसा कानून होना चाहिए! मरने के बाद धर्म संकट में डालकर लूटने वालों की दुकानों पर ताला लगना चाहिए!राजस्थान में कुरीति बन चुकी है मृत्यु भोज?लोगों के तर्क से बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या शोकाकुल परिजनों को मृत्यु भोज के लिए धर्म संकट में डाला जाता है? राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार ने सबसे पहले पुलिस को ट्रोल करने वालों को जवाब दिया। वह बताते हैं-ट्रोल करने वालों में ज्यादातर लोग प्रदेश के बाहर के हैं। शायद इन्हें नहीं पता होगा कि राजस्थान में नुकता यानी मृत्युभोज कितनी बड़ी कुरीति रही है। राजस्थान में शादियों में ढाई-तीन हजार लोगों को आमंत्रित किया जाता है और मृत्युभोज में भी इतनी ही तादाद में भोज कराने का दबाव रहता है। बेशक खाने के आइटम शादी के मुकाबले थोड़े कम होते हैं। यहां तक कि अगर घर

में किसी युवा शख्स की मौत होती है तो भी इतना बड़ा भोज करने का दबाव रहता है। यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को भावनात्मक और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर कर देता है। कई बार तो कर्ज लेना पड़ जाता है। पुलिस की कानूनी बंदिश यह कहती है कि आप सौ-सवा सौ से ज्यादा लोगों को भोज न दें।

साथियों बात अगर हम राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 की मुख्य धाराओं की करें तो, परिभाषा - इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -(ए) मृत्यु भोज का अर्थ है किसी व्यक्ति के निधन के अवसर पर या उसके संबंध में किसी भी अंतराल पर आयोजित या दी जाने वाली दावत और इसमें एक नुक्ता, एक मोसर और एक चहल्लुम शामिल है, और (बी) मृत्यु भोज आयोजित करने या देने' में तैयार या बिना तैयार भोजन की वस्तुओं का वितरण शामिल है, लेकिन इसमें धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष संस्कारों के पालन में परिवार के लोगों या पुरोहित वर्ग के व्यक्तियों या फागीरों को खाना खिलाना शामिल नहीं है, जो कि इससे अधिक नहीं है। कुल मिलाकर सौ व्यक्तियों की संख्या।(3) मृत्यु भोज का निषेध-राज्य में कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज आयोजित नहीं करेगा,न देगा,न शामिल होगा, न ही भाग लेगा।(4) धारा 3 के उल्लंघन के लिए सजा- जो कोई भी धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या ऐसे किसी भी उल्लंघन को करने के लिए उकसाता है, उकसाता है या सहायता करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों के साथ।(5) निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति- यदि धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मृत्यु भोज की व्यवस्था की गई है या होने वाली है या दी जाने वाली है तो ऐसी अदालत आयोजन पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकती है या ऐसे मृत्यु भोज देना (6) धारा 5 के तहत निषेधाज्ञा की अवज्ञा के लिए सजा- जो कोई भी, यह जानते हुए कि धारा 5 के तहत एक आदेश जारी किया गया है, ऐसे निषेधाज्ञा की अवज्ञा करेगा, उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।इस अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी हस्ताक्षर के किसी भी उल्लंघन पर एक वर्ष या पांच रुपये तक की सजा का प्रावधान किया गया है।1000/- या दोनों (7) सरंपच आदि जानकारी देने के लिए बाध्य (1) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 21) के तहत स्थापित ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रत्येक पंच और प्रत्येक पटवारी और लंबरदार धारा 4 या के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम निकटतम मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचित करने के लिए बाध्य होंगे। धारा 6 कोई भी जानकारी जो उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर ऐसे अपराध को करने या करने के इरादे के संबंध में उसके पास हो।(2) ऐसे किसी भी सरपंच, पंच, पटवारी या लंबरदार को उप-धारा (1) के तहत आवश्यक जानकारी देने में विफल रहने पर तीन महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।यह धारा सरपंच और प्रत्येक पंच या ग्राम पंचायत, पटवारी और लंबरदार के लिए धारा 6 में से 5 के तहत अपराध की जानकारी निकटतम प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य बनाती है, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे दंडित भी किया जा सकता है और इस धारा के तहत दोषी ठहराए जाने पर 3 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों।(8) पैसा उधार लेने या उधार देने पर रोक(1) कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज आयोजित करने या देने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति से धन या सामग्री उधार नहीं लेगा या उधार नहीं देगा।(2)इस जानकारी के साथ या यह विश्वास करने का कारण होने पर कि दिए गए ऋण का उपयोग मृत्यु भोज रखने या देने के उद्देश्य से किया जाएगा, दिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए प्रत्येक समझौता शून्य होगा और कानून की अदालत में लागू नहीं किया जाएगा।(9) अपराध का क्षेत्राधिकार और संज्ञान- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, या उस पर मुकदमा नहीं चलाएगी।(10) अभियोजन के लिए परिसीमा- कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं लेगी जिस दिन अपराध होने का आरोप लगाया गया है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है!- जाना पड़ सकता है जेल!राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत मृत्यु भोज कानून दंडनीय है।पारिवारिक सदस्य की मृत्यु पर 13 दिवसीय शोक पर मृत्यु भोज को कुरिति/रीति या धार्मिक संस्कार इसपर बहस छिड़ी-राष्ट्रीय स्तरपर इसका समाधान होना ज़रूरी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने ऑरस सेनेट में पहुंचे रूस के राष्ट्रपति, कितनी सुरक्षित है लिमोजीन कार

ऑरस सेनेट रूस के राष्ट्रपत िपुतिन हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिले। इस दौरान पुतिन जिस कार में गए वह राष्ट्रपति की आधिकारिक कार ऑरस सीनेट है। यह कार क यों दुनिया के सबसे सुरक्षित राष्ट्रपतियों की कारों में से एक है। इसमें किस तरह की सुरक्षा को दिया जाता है। कितना दमदार इंजन दिया जाता है। इसकी बाजार में क या कीमत है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक के राष्ट्रपति हैं। हाल में ही उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से हुई। इस बैठक के लिए ट्रंप जहां एयरफोर्स वन से पहुंचे, वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी लिमोजीन कार से पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति की आधिकारिक कार कौन सी है। इसे कितना सुरक्षित बनाया गया है। किस निर्माता की ओर से इस गाड़ी को बनाया गया है। इसकी बाजार में क्या कीमत होगी। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने कार से पहुंचे पुतिन

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से अलास्का में मुलाकात करने रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी आधिकारिक कार से पहुंचे। यह कार रूस की वाहन निर्माता ऑरस मोटर्स की है जिसे NAMI की ओर से विकसित किया गया है।

क्या है खासियत

रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यह आधिकारिक कार काफी खास है। ऑरस सीनेट कार को राष्ट्रपति के लिए खास तौर पर बनाया गया है इसलिए यह एक आर्मर्ड कार है। जो कार के अंदर बैठे व्यक्ति को बुलेट, ब्लास्ट जैसे किसी भी तरह के हमले से सुरक्षित रख सकती है। इसमें बेहद मजबूत चेसिस और खास सस्पेंशन सिस्टम को लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक यह कार VR10 लेवल की बैलिस्टिक सुरक्षा के साथ आती है।

कैसा है इंटीरियर

जानकारी के मुताबिक ऑरस सीनेट कार का इंटीरियर भी बेहद लग्जरी के साथ आता है। इसके साथ ही इसमें उच्च तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें लग्जरी और आरामदायक सीटें, बेहतरीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेदर अपहोलस्ट्री को दिया गया है।

कितना दमदार इंजन

रूस के राष्ट्रपति के लिए बनाई जाने वाली इस गाड़ी में 4.4-लीटर की क्षमता का हाइब्रिड इंजन V8 मिलता है जो इसे 598 हॉर्स पावर और 889 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ नौ स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया जाता है। यह कार ऑल व्हील ड्राइव भी है और यह 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को सिर्फ छह सेकेंड में पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 249 किलोमीटर प्रति घंटा तक है।

कितनी होगी कीमत

ऑरस सीनेट कार को सबसे पहले 2018 में पेश किया गया था। तब इसकी कीमत करीब 1.32 करोड़ रुपये बताई गई थी। जिसे 2021 में बढ़ाकर करीब 2.40 करोड़ रुपये के आस पास कर दिया गया था। लेकिन राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए किए गए बदलावों के साथ ही इसकी कीमत काफी ज्यादा हो जाती है।

बाइक का इंजन ऑयल कब बदलें? अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है भारी नुकसान, जानें पूरी डिटेल

परिवहन विशेष न्यूज

बाइक इंजन ऑयल भारत में बड़ी संख्या में लोग रोज के कामों को पूरा करने के लिए बाइक का उपयोग करते हैं। बाइक का इंजन सही तरह से काम करता रहे इसके लिए इंजन ऑयल काफी जरूरी होता है। अगर इंजन ऑयल खराब या कम हो जाए तो गंभीर नुकसान भी हो सकता है। इससे बचने के लिए कब इंजन ऑयल को बदलना चाहिए। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश में लोग रोज के कामों को पूरा करने के लिए बाइक का उपयोग करते हैं। कई लोग बाइक का अच्छी तरह ध्यान रखते हैं तो कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं। लापरवाही बरतने पर इंजन को भी नुकसान होता है। कई बार लोग इंजन ऑयल को बिना बदले और चेक किए भी चलाते हैं। लेकिन ऐसा करना कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। इंजन ऑयल को कब बदलना (bike engine oil change) बेहतर रहता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

लापरवाही से नुकसान

किसी भी बाइक में इंजन उसका सबसे जरूरी हिस्सा होता है। इंजन के लिए सबसे जरूरी इंजन ऑयल होता है। कई बार लोग इंजन और इंजन ऑयल को लेकर लापरवाही बरतते हैं। जिससे बाद में उनको भारी नुकसान हो जाता है।

मैनुअल बुक पढ़ना जरूरी

निर्माता की ओर से अपनी हर बाइक के साथ मैनुअल बुक या ई-मैनुअल बुक दी जाती है। बाइक की मैनुअल में हर बात की जानकारी के साथ ही यह भी जानकारी होती है कि किस बाइक में किस तरह के इंजन ऑयल का उपयोग करना चाहिए। साथ में यह भी जानकारी दी जाती है कि इंजन ऑयल को कब बदलना चाहिए। इसे पढ़कर आप इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि इंजन ऑयल को कब बदलना सही होगा।

इंजन से आवाज

अगर आपकी बाइक को चलाते हुए इंजन से सामान्य से ज्यादा आवाज आने लगती है, तो ऐसी स्थिति में इंजन ऑयल को बदलना काफी जरूरी हो जाता है। जब भी बाइक में नया इंजन ऑयल डाला जाता है तो इंजन की आवाज काफी कम हो जाती है, लेकिन जब भी ऑयल खराब हो जाता है तो इंजन से आने वाली आवाज बढ़ने लगती है।

ओवरहीट होने पर भी चेक करें

अगर आपकी बाइक चलते हुए काफी तेजी से ओवरहीट होने लगती है, तो भी इस बात की संभावना होती है कि इंजन ऑयल खराब हो गया हो। इसके साथ ही यह भी खतरा होता है कि इंजन में ऑयल का स्तर काफी कम हो गया हो। ऐसा होने पर इंजन को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे संकेत मिलने पर इंजन ऑयल को चेक कर उसे बदल देना चाहिए।

इस हफ्ते लॉन्च होगी हीरो मोटोकॉर्प की नई बाइक, 125 सीसी सेगमेंट में मुकाबला होगा कड़ा

हीरो की नई बाइक हीरो मोटोकॉर्प की ओर से देश में कई सेगमेंट में बाइक स की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस हफ्ते नई 125 सीसी बाइक को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से किस तरह के फीचर्स और इंजन के साथ नई बाइक को लॉन्च किया जाएगा। इसे किस कीमत पर उपलब्ध करवाया जाएगा। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में कई वाहन निर्माताओं की ओर से कई तरह की बाइक्स की बिक्री की जाती है। प्रमुख वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प भी कई सेगमेंट में अपनी बाइक्स की बिक्री करती है। निर्माता की ओर से इस हफ्ते में एक और नई बाइक को बाजार में लॉन्च (Hero New Bike) करने की तैयारी की जा रही है। इसे किस कीमत, फीचर्स और सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

हीरो लॉन्च करेगी नई बाइक

हीरो मोटोकॉर्प की ओर से भारतीय बाजार में एक और नई बाइक को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से 125 सीसी सेगमेंट में इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा।

टेस्टिंग के दौरान देखी गई थी बाइक

हीरो की नई बाइक को लॉन्च से पहले टेस्ट किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। जिसमें कई फीचर्स की जानकारी मिली थी।

कैसे होंगे फीचर्स

निर्माता की ओर से अभी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन टेस्टिंग के दौरान देखी गई यूनिट को क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर के साथ देखा गया था। जिससे यह पता चलता है कि हीरो की नई बाइक में कारों वाले इस क्रूज कंट्रोल फीचर के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एलईडी हेडलाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स को दिया जाएगा।

कितना दमदार इंजन

नई बाइक में हीरो का 125 सीसी का मौजूदा इंजन दिया जा सकता है। इसमें 124.7 cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन का उपयोग किया जा सकता है। जिससे इस बाइक को 10 हॉर्स पावर और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है। इस इंजन के साथ निर्माता की ओर से पांच स्पीड गियरबॉक्स को दिए जाने की उम्मीद है।

कब होगी लॉन्च

निर्माता की ओर से अभी औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि हीरो की नई बाइक को भारत में 19 और 20 अगस्त तक लॉन्च किया जा सकता है। इसे ग्लैमर नाम से ही लाया जा सकता है।

किनसे होगा मुकाबला

हीरो की नई बाइक को बाजार में 125 सीसी सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। इस बाइक का बाजार में सीधा मुकाबला होंडा शाइन 125, एसपी 125, बजाज पल्सर 125, टीवीएस जैसी बाइक्स

रूस के राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे ट्रंप, साथ में किया खास कार में सफर, कितनी सुरक्षित है 'द बीस्ट'

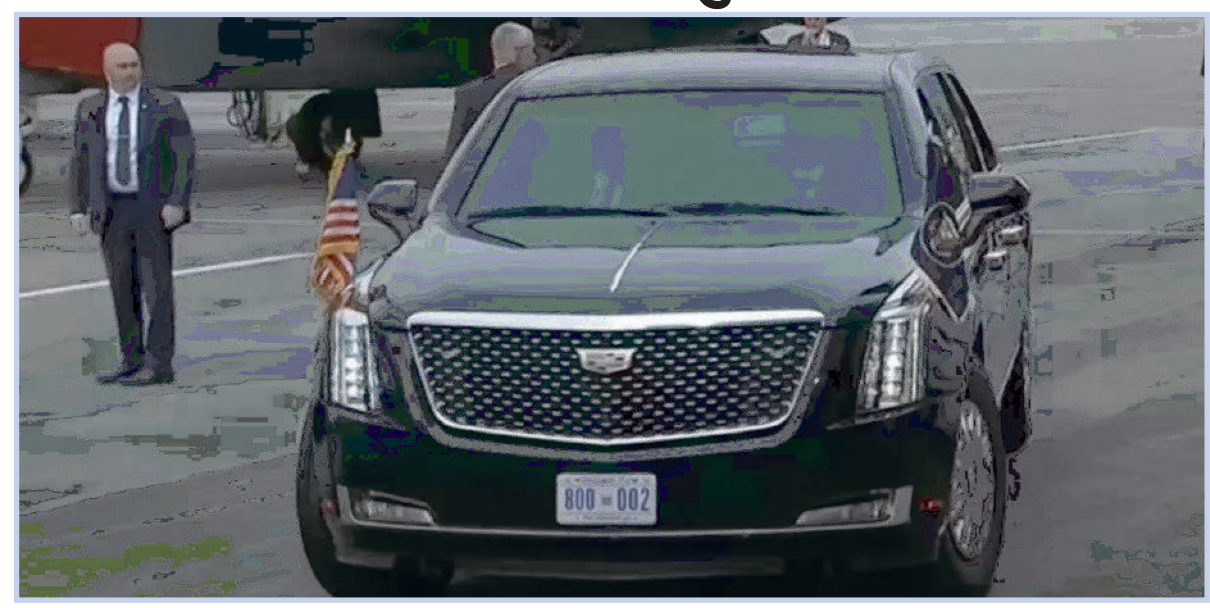

पुतिन-ट्रम्प बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हाल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का में मिले। इस दौरान दोनों नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक कार The Beast में सवारी की। इस कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक क यों कहा जाता है। इसमें किस तरह की सुरक्षा को दिया जाता है। कितना दमदार इंजन दिया जाता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं। फिलहाल इस पद पर डोनाल्ड ट्रंप हैं और उनके पास दुनिया की सबसे सुरक्षित कार द बीस्ट भी है। ट्रंप ने हाल में ही अलास्का का दौरा किया जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बैठक हुई। इस दौरान वह अपनी आधिकारिक कार द बीस्ट में नजर आए। यह कार कितनी सुरक्षित है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

ट्रंप और पुतिन की हुई मुलाकात

अलास्का में हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों अपनी अपनी आधिकारिक कारों के साथ नजर आए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की आधिकारिक कार ऑरस सीनेट है तो अमेरिका के राष्ट्रपति की आधिकारिक कार द बीस्ट है।

कितनी सुरक्षित है द बीस्ट

द बीस्ट जनरल मोटर्स की ओर से खास तौर पर बनाई गई कैडिलैक लिमोजीन कार है। जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पर न तो गोली और न ही बम-बारूद का असर होता है। जिसकी वजह से यह एक बख्तरबंद कार के रूप में भी जाना जाता है। इस कार को सैन्य ग्रेड ऑर्मर से लैस किया गया है, जो पांच इंच मोटा है। इसके दरवाजे आठ इंच मोटे हैं और इनका वजन एक बोइंग 757 जेट के केबिन डोर के बराबर है।

कितना दमदार इंजन

अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक कार के तौर पर उपयोग की जाने वाली द बीस्ट में काफी दमदार इंजन दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक इसमें आठ हजार सीसी की क्षमता का डीजल इंजन दिया जाता है जिससे 800 बीएचपी की पावर मिलती है। इसके दमदार इंजन और सुरक्षा फीचर्स के कारण इसका वजन नौ हजार किलोग्राम से ज्यादा हो जाता है।

कितनी है कीमत

आमतौर पर राष्ट्रपति के लिए बनाई जाने वाली कार में कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली द बीस्ट की कीमत करीब 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आस पास है।

गाड़ी का स्टेयरिंग वाइब्रेट हो रहा है तो हो जाएं सावधान, ये हैं 4 बड़े कारण, जिनकी वजह से हो सकता है भारी नुकसान

कार स्टीयरिंग कंपन भारत में बड़ी संख्या में लोग कार का उपयोग करते हैं। लेकिन काफी कम लोगों को ही सही तरह से कार चलाना आता है। अगर आप भी लापरवाही से कार चलाते हैं तो कई बार कार के स्टेयरिंग में वाइब्रेशन की समस्या आ जाती है। कार में यह समस्या किन कारणों से होती है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार का उपयोग करते हैं। कई बार छोटी लापरवाही के कारण भी कार में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। ऐसी ही एक परेशानी स्टेयरिंग में वाइब्रेशन की होती है। यह परेशानी किस तरह की लापरवाही के कारण होती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

सस्पेंशन में खराबी आना

जब कार को लंबे समय तक खराब सड़कों पर चलाया जाता है। तो कार के सस्पेंशन में खराबी आने का खतरा बढ़ जाता है। अगर एक बार सस्पेंशन में खराबी आ जाती है तो फिर गाड़ी चलाने पर स्टेयरिंग में वाइब्रेशन की समस्या होने लगती है। अगर इस समस्या को समय रहते दूर न करवाया जाए तो फिर गाड़ी में और भी कई तरह की परेशानियों के आने का खतरा बढ़ जाता है। जिसे ठीक करवाने में समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं।

ब्रेक रोटर में खराबी

गाड़ी को चलाने का सही तरीका काफी कम लोगों को पता होता है। ज्यादातर लोग जब कार में ब्रेक लगाते हैं तो वो काफी तेज ब्रेक लगाते हैं। जिससे कार के ब्रेक रोटर में खराबी आ जाती है। जब ब्रेक रोटर खराब हो जाए तो भी कार चलाते हुए स्टेयरिंग में वाइब्रेशन होने लगता है। ब्रेक रोटर और ब्रेक पैड मिलकर ही कार को रोकते या स्पीड को कम करते हैं। लेकिन इनके खराब होने पर स्टेयरिंग में वाइब्रेशन हो जाता है।

अलाइनमेंट आऊट होना

गाड़ी के स्टेयरिंग में वाइब्रेशन को दूर रखने के लिए अलाइनमेंट का सही होना भी जरूरी होता है। गाड़ी के पहियों का अलाइनमेंट जब आऊट हो जाए तो कार चलाते हुए स्टेयरिंग में वाइब्रेशन होने की समस्या आ जाती है। ऐसा होने पर कार एक दिशा में जाने लगती है। साथ ही वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। इससे बचने के लिए समय समय पर कार के अलाइनमेंट को चेक करवाना चाहिए। ऐसा करने से स्टेयरिंग में वाइब्रेशन की समस्या को दूर रखा जा सकता है।

लापरवाही बरतने पर

अगर कार चलाते हुए लापरवाही बरती जाए और लंबे समय तक गाड़ी को खराब सड़कों, खराब ड्राइविंग पैटर्न के साथ चलाया जाता है तो भी स्टेयरिंग में वाइब्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही कई बार ऐसा मौसम में काफी ज्यादा बदलाव के कारण भी होने लगता है।

क्या अब स्टेट हाईवे के लिए अलग से फास्टैग लेना पड़ेगा? वहां टोल शुल्क कैसे कटेगा?

क्या सालाना फास्टैग पास लेने के बाद स्टेट हाईवे पर यात्रा करने के लिए अलग से फास्टैग लेना जरूरी होगा? जानिए स्टेट हाईवे पर टोल कैसे कटेगा?

15 अगस्त से पूरे देश में FASTag Annual Pass (फास्टैग वार्षिक पास) शुरू हो गया है। यानी अब अगर कोई गाड़ी इस पास के जरिए हाईवे से गुजरेगी तो उसे 1 साल में 200 ट्रिप तक अलग से टोल नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए एकमुश्त 3000 रुपये पहले से भरने होंगे।

कहां-कहां मान्य होगा वार्षिक पास

15 अगस्त से शुरू हुआ यह फास्टैग वार्षिक पास सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) (एनएचएआई) द्वारा संचालित हाईवे, एक्सप्रेसवे और सड़कों पर ही मान्य होगा। इसका मतलब है कि यह पास किसी भी स्टेट हाईवे, राज्य सरकार की सड़कों या प्राइवेट टोल रोड्स पर लागू नहीं होगा।

स्टेट हाईवे पर अलग पास की जरूरत है या नहीं?

कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या अब स्टेट हाईवे पर यात्रा करने के लिए अलग पास बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वार्षिक पास वहां काम नहीं करेगा। तो इसका जवाब है - नहीं। इसके लिए अलग से कोई पास लेने की जरूरत नहीं है।

दरअसल, वार्षिक पास सीधे आपके गाड़ी में लगे फास्टैग से जुड़ा रहेगा। यानी अगर आप एनएचएआई के हाईवे पर चलेंगे तो वहां वार्षिक पास लागू होगा और टोल नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही आप स्टेट हाईवे पर आएंगे, वहां का टोल आपके सामान्य फास्टैग बैलेंस से कटेगा।

कैसे कटेगा टोल स्टेट हाईवे पर

अगर आप एनएचएआई के हाईवे पर सफर करते हुए बीच में स्टेट हाईवे पर जाते हैं, तो वहां का टोल अपने-आप आपके फास्टैग से कट जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आपके फास्टैग वॉलेट में हमेशा पर्याप्त बैलेंस मौजूद हो।

किसके अधीन होते हैं स्टेट हाईवे

स्टेट हाईवे पर टोल वसूली का सिस्टम राज्य सरकार या निजी ऑपरेटरों के हाथ में होता है। यह एनएचएआई या सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। इसी वजह से वार्षिक पास वहां लागू नहीं होता।

फास्टैग रिचार्ज रखें

यानि साफ है कि वार्षिक फास्टैग पास सिर्फ एनएचएआई के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य है। स्टेट हाईवे पर इसके लिए कोई अलग पास लेने की जरूरत नहीं है। वहां भुगतान सामान्य फास्टैग से होगा, बस ध्यान रखें कि उसमें बैलेंस होना चाहिए।

ग्रामीण विकास को गति देती पंचायतें

विजय गर्ग

भारत में पंचायत को सुशासन की दृष्टि से देखें, तो लोक सशक्तीकरण इसकी पूर्णता है और लोक विकेंद्रीकरण की नजर से देखें, तो यह एक ग्रामीण स्वशासन की परिपाटी की पूर्ति है जो ग्रामीण विकास के लिए कहीं अधिक जरूरी है। इतना ही नहीं यह गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने को भी बल देता है। सुशासन शांति और खुशहाली का परिचायक है। जबकि पंचायत एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण स्वराज को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में 6.65 लाख गांव हैं, जिनमें 2.68 लाख ग्राम पंचायतें और ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं, जो देश के ग्रामीण परिदृश्य का आधार हैं। पंचायतें ग्रामीण विकास को गति दे ही रही हैं, आम आदमी की भी ताकत बन रही हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास को रफ्तार देने और केंद्रित कार्यक्रमों तथा निवेशों के जरिए समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहल की गई। मसलन वर्ष 2028 तक के लिए जीवन मिशन, ब्राडबैंड सुविधा, जिसका लक्ष्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक इंटरनेट पहुंच उपलब्ध हो तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जाए। इसके अतिरिक्त भारतीय डाक उद्यमियों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई और स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करने वाले एक प्रमुख सार्वजनिक 'लाजिस्टिक्स' संगठन के रूप में विकसित करना भी लक्ष्य है। ग्रामीण समृद्धि एवं अनुकूलन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, हाशिए पर पड़े समुदायों और भूमिहीन परिवारों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है।

पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिचायक है और सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी नींव है। पंचायत जैसी संस्था की बनावट कई प्रयोगों और अनुप्रयोगों का भी नतीजा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विफल होना और इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति का गठन फिर वर्ष 1957 में उसी की रपट पर इसका मूर्त रूप लेना देखा जा सकता है। गौरतलब है कि जिस पंचायत को राजनीति से परे और नीति उन्मुख सजग प्रहरी की भूमिका में समस्या दूर करने का एक माध्यम माना जाता है, आज वही कई समस्याओं से जकड़ी हुई है। जिस पंचायत ने सबसे नीचे के लोकतंत्र को कंधा दिया हुआ है, वही कई जंजालों से मुक्त नहीं है, चाहे वित्तीय संकट हो या उचित नियोजन की कमी या फिर अशिक्षा, रूढ़िवादिता तथा पुरुष वर्चस्व के के साथ जाति और ऊंच-नीच के पूर्वाग्रह ही क्यों न हों। यह समस्या पिछले तीन दशकों में घटी तो है और इसी पंचायत यह सिद्ध भी किया है कि उसका कोई विकल्प नहीं है।

पंचायत की । व्याख्या में क्षेत्र विशेष में शासन करने का विशिष्ट अधिकार निहित है। इसी अधिकार से उन दायित्वों की पूर्ति होती है जो ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत स्वशासन का बहाव भरता है और ग्रामीण बदलाव की गाढ़ी रेखा खींचता है। वर्ष

1997 का नागरिक घोषणापत्र सुशासन का ही शिखर था और 2005 में सूचना का अधिकार इसी का अगला अध्याय इतना ही नहीं वर्ष 2006 की ई-गवर्नेंस योजना भी सुशासन की रूपरेखा को ही विस्तृत नहीं करती, बल्कि इनसे पंचायत को भी ताकत मिलती है। वर्ष 1992 में सुशासन की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटेन में सामने आई थी। वर्ष 1991 में उदारीकरण के बाद इसकी पहल भारत में भी देखी गई। सुशासन के इसी वर्ष में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया जा रहा था। संविधान के 73वें संशोधन में जब इसे संवैधानिक स्वरूप दिया गया, तब वर्ष 1959 से राजस्थान के नागौर से यात्रा कर रही यह पंचायत रूपी संस्था नए आभामंडल से युक्त हो गई। वर्ष 1992 में हुए इस संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया।

स्वशासन के संस्थान के रूप में इसकी व्याख्या दो तरीके से की जा सकती है। पहला संविधान में इसे सुशासन के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका सीधा मतलब स्वायत्तता और क्षेत्र विशेष में शासन करने का पूर्ण अधिकार है। दूसरा यह प्रशासनिक संघीयकरण को मजबूत करता है। गौरतलब है कि संविधान के इसी संशोधन में गांधी के ग्राम स्वराज को पूरा किया, मगर क्या यह बात भी पूरी शिद्दत से कही जा सकती है कि स्वतंत्र भारत की अति महत्त्वाकांक्षी संस्था स्थानीय स्वशासन से परिपूर्ण है। पंचायतों में एक तिहाई महिलाओं का आरक्षण इसी संशोधन के साथ सुनिश्चित कर दिया गया था जो मौजूदा समय में पचास फीसद तक है। देखा जाए तो तीन दशक से अधिक पुरानी संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। राजनीतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतिनिधियों के प्रति रूढ़िवादी सोच में अच्छा खासा बदलाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वे भय, संकोच और घबराहट को दूर करने में कामयाब भी रही हैं।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही परिणाम है कि पंचायतों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। महिलाओं की भागीदारी भी सामने आ रही है। मगर राजनीतिक माहौल में अपराधीकरण, बाहुबल, जातिवाद और ऊंच-नीच आदि दुर्गुणों से पंचायतें मुक्त नहीं है। समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन भी शासन की एक कड़ी है। इसका लक्ष्य ऐसे समाज का निर्माण करना जहां शोषण और सुशासन का प्रभाव हो, जिससे पंचायत में पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके। वर्ष 2011 1 की जनगणना के अनुसार देश में चौथा व्यक्ति अभी भी अशिक्षित है। पंचायत और सुशासन पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। कई महिला प्रतिनिधि ऐसी हैं जिनको पंचायत के नियम पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है। डिजिटल इंडिया का संदर्भ भी 2015 से देखा जा सकता है। आनलाइन क्रियाकलाप और डिजिटलीकरण ने पंचायत से जुड़े ऐसे प्रतिनिधियों के लिए कमोबेश चुनौती पैदा है। हालांकि देश की ढाई लाख से अधिक पंचायतों में काफी हद तक डिजिटल संपर्क बाकी है। साथ ही बिजली आदि की आपूर्ति का कमजोर होना भी इसमें एक बाधा है।

डिजिटल क्रांति ने सुशासन पर गहरी छाप छोड़ी है। डिजिटल लेन-देन में तेजी आई है, कागजों के आदान-प्रदान में बढ़ोतरी हुई है, भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हो रहा है। फसल बीमा कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं में दावों के निपटारे के लिए 'रिमोट सेंसिंग', एआइ और 'माडलिंग टूल्स' का प्रयोग होने लगा है। वहीं ग्राम पंचायतों में खुले स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे ग्राम स्तरीय उद्यमी बनें सूचना और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए शासन की प्रक्रियाओं का पूर्ण रूपांतरण ही 'ई-गवर्नेंस' कहलाता है, जिसका लक्ष्य आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हुए पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि व है कि राष्ट्रीय-गवर्नेंस कार्यक्रम अंतर्गत प्रारंभ में 31 सेवाएं शामिल की थीं। इस प्रकार की अवधारणा सुशासन की परिपाटी को भी सुसज्जित करती है। पंचायती राज व्यवस्था आम लोगों । की ताकत है और खास प्रकार की राजनीति से दूर है। यह ऐसी व्यवस्था है जो स्वयं द्वारा स्वयं पर शासन किया जाता है। बीते तीन दशकों में पंचायतें बदली हैं। इन सब में एक प्रमुख बात यह रही है कि महिलाएं तुलनात्मक रूप से अधिक सक्रिय हुई हैं। राज्य सरकारों का ऐसी संस्थाओं पर भरोसा बढ़ा है। गांवों में विकास को रफ्तार देने में इनकी भूमिका बढ़ी है।

मुनीर की 'गीदड़ भभकी'

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एवं सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर एक कट्टरपंथी मौलवी ज्यादा हैं और एक पेशेवर सेनाध्यक्ष कम लगते हैं। वह दो माह के अंतराल में दूसरी बार अमरीका के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात भी तय है। क्या अमरीकी राष्ट्रपति ने 'व्हाइट हाउस' में राष्ट्राध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष के बजाय सेना के जनरल से द्विपक्षीय मुलाकात की परंपरा शुरू कर दी है? जनरल मुनीर को अमरीका की सरजमीं से परमाणु हमले की धमकी देने की अनुमति क्यों दी गई? अमरीका तो भारत का मित्र और रणनीतिक साझेदार देश है। बेशक टैरिफ के मुद्दे पर विवाद है, लेकिन अमरीका 'क्वाड' जैसे संगठन में भी भारत का साथी देश है। 'क्वाड' का शिखर सम्मेलन भारत में ही होना है। ट्रंप उसे टाल नहीं सकते। बहरहाल पाक समुदाय को संबोधित करते हुए मुनीर ने लगभग पूरी दुनिया को धमकाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। यदि हम सोचते हैं कि हम हार रहे हैं, तो उससे पहले हम आधी दुनिया को नष्ट कर देंगे।'' मुनीर के कथन के भाव यही थे। हालांकि उनका संबोधन अंग्रेजी भाषा में था। इससे पहले मुनीर ने सीधे भारत को धमकी दी थी कि हम सिंधु पर बांध बनाने का इंतजार कर रहे हैं। यदि ऐसा किया गया, तो हम बांध पर 10 मिसाइलों से हमला करेंगे। हमारे पास बहुत मिसाइलें हैं।'' भारत ने मुनीर के इन शब्दों को 'गीदड़ भभकी' के तौर पर लिया और एक बार फिर साफ किया कि भारत परमाणु हमले की 'ब्लैकमेल' से नहीं डरता। कारगिल और 'ऑपरेशन सिंदूर' के युद्धनुमा संघर्षों के दौरान भी पाकिस्तान परमाणु शक्ति वाला देश था।

मुनीर अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह घुटनों पर आना पड़ा? सबसे गौरतलब यह है कि आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर अमरीका और राष्ट्रपति ट्रंप का नजरिया क्यों बदल गया है? ट्रंप ने पहले राष्ट्रपति-काल के दौरान ही पाकिस्तान की अरबों डॉलर की आर्थिक मदद रद्द कर दी थी। तो क्या अब पाकिस्तान आतंकवाद-मुक्त देश लगता है? राष्ट्रपति ट्रंप इतना जरूर समझ लें कि पाकिस्तान के जनरल के प्रस्ताव पर ही उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने वाला नहीं है। फर्जी युद्धविराम के दावों के आधार पर भी सर्वोच्च शांति पुरस्कार से नहीं नवाजा जा सकता। नोबेल पुरस्कार समिति और ज्यूरी को सब जानकारियां होती हैं। अमरीकी राष्ट्रपति पाकिस्तान में क्या करना चाहते हैं, यह भी समूचे विश्व के संज्ञान में है। दरअसल अपने वजूद के 78 सालों के बावजूद पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत और खासकर फौज 'भारत-ग्रंथि' से मुक्त नहीं हो पाई है। जनरल मुनीर ने अमरीका में कश्मीर पर वही जहर उगला है, जो पहलगाम नरसंहार से पहले एक और संबोधन में किया था। क्या सेना प्रमुख का यह भी काम होता है कि वह पाक समुदाय को भडक़ाए और सुलगाए? मुनीर के बयान बता रहे हैं कि उसकी महत्वाकांक्षा क्या है? पाकिस्तान का इतिहास उसके जनरलों की ऐसी महत्वाकांक्षाओं और उनकी कारस्तानियों से भरे हैं। मुनीर के संबोधन समझा रहे हैं कि आने वाला युद्ध 'नई किस्म' का होगा। यह 'आर्थिक युद्ध' भी हो सकता है, क्योंकि मुनीर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की गुजरात के जामनगर में स्थित रिफाइनरी को निशाना बनाने की कसम खाई है। यह विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। मुनीर हरेक संदर्भ में पाकिस्तान को भारत का प्रतिद्वंद्वी देश चित्रित करना चाहता है, जबकि यथार्थ बिल्कुल भिन्न है। भारत की जीडीपी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से 10 गुना ज्यादा है और यह अंतर चौड़ा होता जा रहा है। विश्व में भारत का जो दर्जा है, पाकिस्तान उस संदर्भ में दूर-दूर तक भी नहीं है। पाकिस्तान सब कुछ उधार मांग कर जीने वाला देश है। मुनीर सपने देखना चाहते हैं, तो कोई क्या कर सकता है?

मौन वेदना

विजय गर्ग

अक्सर हम सुनते हैं कि बुढ़ापा जीवन का दूसरा बचपन होता है । पर क्या यह सचमुच उतना ही निर्दोष, निश्चित और आनंदमय होता है ? दरअसल, यह जीवन का वह पड़ाव है, जहां देह की शक्ति क्षीण होती है और आत्मा की अग्नि भी मंद पड़ने लगती है । यह वह समय है, जब कभी अपनी अंगुलियों पर नचाने वाली दुनिया, उन्हीं अंगुलियों को सहारा देने से भी कतराती है। यह वह समय है जब जीवन का अनुभव, जो कभी ज्ञान का पर्याय था, आज बोझ लगने लगता है । वृद्धों की पीड़ा केवल शारीरिक नहीं होती, यह आत्मा की गहराइयों तक उतरती है, हृदय को छलनी करती है । यह वह चीख है जो होठों तक नहीं आती । वह आंसू है जो पलकों से नहीं बहता । वह दर्द है जो किसी से कहा नहीं जाता। उनकी अनकही दास्तान समाज के उस अदृश्य कोने में दबी पड़ी है, जहां कभी सम्मान का सूरज उगता था, पर अब केवल उपेक्षा की अंधेरी रात पसरी है ।

आज के परिवेश में, जहां गति ही जीवन का पर्याय है, वृद्ध अक्सर पीछे छूट जाते हैं। उस तेज रफ्तार ट्रेन में बैठे मुसाफिर से लगते हैं, जिसकी मंजिल तो करीब है, पर साथी छूटते जा रहे हैं । यजुर्वेद का कथन है कि हम सौ शरद ऋतुओं तक जिएं। यह कामना तो है। पर क्या वह जीवन सौ शरद ऋतुओं तक सम्मान और प्रेम से भरा होगा ? आज का वृद्ध अपने ही घर में अजनबी हो जाता है। जिस घर को उसने अपने पसीने से सींचा, जिस आंगन में उसने अपने बच्चों को खेलते देखा, आज उसी आंगन में उसे एक किनारे धकेल दिया जाता है। उनकी बातें अनसुनी कर दी जाती हैं, उनके अनुभव को बेमानी ठहरा दिया जाता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तब यक्ष ने उत्तर दिया था, 'हर दिन प्राणी मरते हैं, फिर भी शेष अमरत्व की इच्छा करते हैं ।'

मगर कई वृद्ध अपनी आंखों के सामने अपनी उपयोगिता, अपने अस्तित्व को मिटता देखते हैं । यह कैसी विडंबना है कि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, उन्हीं हाथों को आज सहारे की जरूरत पड़ती है, तो हम अपनी आंखें फेर लेते हैं ।

उपेक्षा ही उनकी वेदना का एक पहलू नहीं । क्या हमने कभी उस बूढ़ी आंखों में झांका है, जहां कभी भविष्य के सपने तैरते थे, पर अब केवल एक धुंधली उदासी पसरी है ? आधुनिक जीवन शैली ने उन्हें अकेला कर दिया है, एक ऐसे द्वीप पर जहां संचार के सारे साधन होकर भी वे निशब्द हैं। बच्चे करिअर की दौड़ में ऐसे व्यस्त हैं कि उनके पास माता-पिता के लिए दो पल बात करने का भी समय नहीं। वृद्धों ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दिया, बिना किसी फल की आशा के। पर आज जब उन्हें प्रेम, सहारा और सहानुभूति के फल की उम्मीद है, तो वे खाली हाथ रह जाते हैं । वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या इस कटु सत्य का चीख-चीखकर प्रमाण दे रही है कि हमारा समाज अपनी जड़ों से कितनी दूर जा रहा है। ये वृद्धाश्रम केवल ईंट-पत्थर के भवन नहीं, बल्कि उन सपनों, आशाओं, रिश्तों के टूटने की हृदयविदारक कहानियां हैं, जिन्हें कभी अटूट माना जाता था। वे वहां केवल शारीरिक रूप से नहीं रहते, बल्कि एक गहन मानसिक और भावनात्मक सूनेपन में जीते हैं, जैसे कोई पतझड़ में सूखा पत्ता हो, जिसकी शाखाएं टूट चुकी हों ।

वृद्धों के अनुभवों का विशाल भंडार, जिसे कभी समाज की धरोहर माना जाता था, आज उनके ज्ञान को 'पुरानी बातें' कहकर दरकिनार कर दिया जाता है । वृद्धों के मन में सिर्फ थोड़ा-सा प्रेम, थोड़ा-सा सम्मान और साथ की इच्छा होती है। पर क्या हम उन्हें यह प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं? उनकी जिंदगी की किताब के पन्ने आज खुद-ब-खुद पलटने के बजाय बिखरे हुए महसूस हो रहे हैं । यह पीड़ा तब और गहरी हो जाती है, जब वे देखते हैं कि समाज का हर वर्ग उनके प्रति असंवेदनशील होता जा रहा है, मानो वे कोई अनावश्यक बोझ हों, जिनके अस्तित्व से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता । सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें मिलने वाला थोड़ा- सा सम्मान भी कम होता जा रहा है। अस्पतालों, बैंकों या किसी भी सरकारी दफ्तर में उन्हें अक्सर कतारों में खड़ा देखा जा सकता है, उनकी कांपती टांगें और झुकी हुई कमर इस बात की गवाही देती हैं कि उनकी शारीरिक शक्ति उन्हें इसकी इजाजत नहीं देती। यह सब कुछ उन्हें एक बोझिल अहसास दिलाता है, जैसे वे इस दुनिया, समाज या अपने ही परिवार पर एक अनावश्यक बोझ हों । वृद्धों की चुप्पी, उनकी निस्तेज आंखें और उनके अधखुले होंठों पर ठहरी शिकायतें, एक ज्वलंत प्रश्न बन कर खड़ी हैं- क्या यही है मानव सभ्यता का चरम विकास, जहां प्रेम और करुणा की जगह व्यावसायिकता ने ले ली है ?

आज आवश्यकता है कि हम अपनी आंखें खोलें, अपने हृदय के द्वार खोलें और वृद्धों की इस अनकही दास्तान को सुनें । यह केवल उनकी नहीं, बल्कि हम सबके भविष्य की कहानी है, क्योंकि एक दिन हम सब भी इसी पड़ाव पर होंगे। हमें याद रखना होगा कि जिस नींव पर आज हम खड़े हैं, उसे हमारे वृद्धों ने ही अपने खून-पसीने से सींचा है। उनके प्रति हमारा दायित्व केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। यह केवल उन्हें सहारा देने की बात नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी मानवीयता और अपने मूल्यों को बचाने की बात है। उन्हें वह सम्मान, वह प्रेम और वह सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है, जिसके वे हकदार हैं, ताकि उनकी शेष यात्रा पीड़ादायी नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण और गरिमामय हो ।

गांवों में महिलाओं को सशक्त बनाना

विजय गर्ग

गांवों में महिलाओं को सशक्त बनाना वैश्विक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, न केवल लैंगिक समानता को संबोधित करना, बल्कि गरीबी में कमी, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण भी। इसे प्राप्त करने की रणनीतियाँ बहुआयामी हैं और एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो ग्रामीण समुदायों में मौजूद अनूठी चुनौतियों और अवसरों पर विचार करता है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा मुख्य चुनौतियां:

शिक्षा तक सीमित पहुंच: ग्रामीण महिलाओं के बीच उनके पुरुष समकक्षों और शहरी महिलाओं की तुलना में कम साक्षरता दर। यह जानकारी तक पहुंचने, निर्णय लेने में भाग लेने और बेहतर आर्थिक अवसरों को सुरक्षित करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।

आर्थिक निर्भरता: कई ग्रामीण महिलाएं अवैतनिक श्रम में लगी हुई हैं, जैसे कि घर के काम और कृषि कार्य, जिन्हें अक्सर आर्थिक आंकड़ों में मान्यता नहीं दी जाती है। संसाधनों और आय पर उनका सीमित नियंत्रण है, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं।

हेल्थकेयर और स्वच्छता की कमी: स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुंच महिलाओं और लड़कियों को असंगत रूप से प्रभावित करती है, जिससे मातृ मृत्यु दर और अन्य

स्वास्थ्य मुद्दों की उच्च दर होती है।

सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड: गहरी जड़ें पितृसत्तात्मक प्रणाली और पारंपरिक रीति-रिवाज अक्सर महिलाओं की गतिशीलता, निर्णय लेने की शक्ति और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं। इससे लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव हो सकता है।

सीमित राजनीतिक भागीदारी: ग्रामीण महिलाओं को अक्सर स्थानीय शासन और राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में रेखांकित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं को नीति में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है। सशक्तिकरण के लिए रणनीतियाँ: इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई पहलों को लागू किया जा सकता है:

आर्थिक सशक्तिकरण:

माइक्रोफाइनेंस और क्रेडिट: महिलाओं को अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए छोटे ऋण और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना, जैसे पशुधन खेती, हस्तशिल्प, या छोटे पैमाने पर खुदरा।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण: सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल साक्षरता और स्थायी कृषि तकनीकों जैसे बाजार-प्रासंगिक कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना।

स्व-सहायता समूह (एसएचजी) की स्थापना: ये समूह महिलाओं को अपनी बचत, एक्सेस क्रेडिट और सामूहिक रूप से सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम बनाते हैं। वे सामाजिक संपर्क और आपसी समर्थन के लिए एक मंच के रूप में भी काम करते हैं।

महिला-एलईडी उद्यमों को बढ़ावा देना: महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बाजार संबंध और समर्थन प्रणाली बनाना, उन्हें मूल्य श्रृंखला पर अधिक नियंत्रण हासिल करने में मदद करना।

शिक्षा और जागरूकता:

गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच में सुधार: ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण और रखरखाव, लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, और एक सुरक्षित और सहायक सीखने के माहौल को सुनिश्चित करना।

वयस्क साक्षरता कार्यक्रम: वयस्क महिलाओं को अपने पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक कौशल में सुधार करने के लिए कार्यात्मक साक्षरता कक्षाओं का संचालन करना।

स्वास्थ्य और स्वच्छता शिक्षा: महिलाओं की समग्र भलाई में सुधार के लिए प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और रोग की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

डिजिटल साक्षरता: जानकारी का उपयोग करने, बाजारों से जुड़ने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट के उपयोग में महिलाओं को प्रशिक्षित करना।

सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण:

कानूनी जागरूकता: महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना, जिसमें भूमि अधिकार, विरासत कानून और घरेलू हिंसा से सुरक्षा शामिल है।

नेतृत्व प्रशिक्षण: महिलाओं को स्थानीय शासन निकायों (जैसे, ग्राम परिषदों, पंचायतों) में भाग लेने और नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रशिक्षित करना।

पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देना: लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व के बारे में बातचीत

कृषि सुधार के 78 वर्ष: स्वतंत्रता के बाद से कृषि में भारत की उल्लेखनीय यात्रा

विजय गर्ग

स्वतंत्रता के बाद से कृषि में भारत की यात्रा एक उल्लेखनीय और परिवर्तनकारी रही है, जिसे सुधारों और नीतियों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया है जिसने देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक परिदृश्य को फिर से आकार दिया है। भोजन की कमी से जूझ रहे देश से लेकर एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक और निर्यातक बनने तक, भारत के कृषि सुधार इसकी विकास कहानी की आधारशिला रहे हैं। फाउंडेशन वर्ष (1947-1960): स्क्रैच से भूमि सुधार और भवन स्वतंत्रता के समय, भारत के कृषि क्षेत्र की विशेषता कम उत्पादकता, एक शोषक भूमि कार्यकाल प्रणाली और मानसून की बारिश पर भारी निर्भरता थी। सरकार का प्रारंभिक ध्यान इन मूलभूत मुद्दों को संबोधित करने पर था।

बिचौलियों का उन्मूलन: पहला बड़ा कदम जमींदारी प्रणाली को समाप्त करना था, जिसने गैर-खेती करने वाले जमींदारों का एक वर्ग बनाया था। इस सुधार का उद्देश्य टिलर को भूमि का मालिक बनाना था, जिससे उन्हें अपने खेतों में निवेश करने और सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

भूमि छत और पुनर्वितरण: भूमि जोत के आकार पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कानून बनाए गए थे जो एक व्यक्ति स्वयं कर सकता था। अधिशेष भूमि को तब भूमिहीन किसानों को पुनर्वितरित किया गया था। जबकि इन सुधारों का कार्यान्वयन राज्यों में भिन्न था, उन्होंने अधिक न्यायसंगत कृषि संरचना के लिए आधारशिला रखी।

प्रारंभिक योजना: कृषि को प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) में उच्च प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें सिंचाई परियोजनाओं में महत्वपूर्ण सार्वजनिक निवेश, जैसे भाखड़ा बांध, और कृषि अनुसंधान और विकास के लिए संस्थानों की स्थापना थी। हरित क्रांति (1960s-1970s): आत्मनिर्भरता की ओर एक छलांग 1960 के दशक में भोजन की गंभीर कमी का दौर था, जिससे शिप-टू-माउथ अस्तित्व बन गया, जहां भारत खाद्य सहायता पर बहुत अधिक निर्भर था। इस संकट ने हरित क्रांति के शुभारंभ में समापन करते हुए नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव को प्रेरित किया। उच्च उपज वाली किस्में : हरित क्रांति गेहूं और चावल के बीज की नई, उच्च उपज वाली किस्मों की शुरूआत से प्रेरित थी। इन्हें एक पैकेज दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया था जिसमें आधुनिक खेती तकनीक, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक शामिल थे।

सिंचाई और मशीनीकरण: सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक सिंचाई सुविधाओं, जैसे नलकूपों और यंत्रीकृत कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया।

संस्थागत सहायता: भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और कृषि मूल्य आयोग (अब सीएसीपी) जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना किसानों के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने, बफर स्टॉक बनाए रखने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। हरित क्रांति एक अभूतपूर्व सफलता थी, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। इसने भारत को खाद्य-घाटे से खाद्य-अधिशेष राष्ट्र में बदल दिया, जिससे खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। हालांकि, इसने पानी की कमी और मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ क्षेत्रीय विषमताओं और

पर्यावरणीय चिंताओं को भी जन्म दिया। हरित क्रांति के बाद का युग (1980s-2000s): विविधीकरण और उदारीकरण हरित क्रांति की सफलता के बाद, इन लाभों को अन्य फसलों और क्षेत्रों में विस्तारित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की दिशा में ध्यान केंद्रित किया गया।

खाद्यान्न से परे क्रांतियाँ: इस अवधि में अन्य लक्षित कार्यक्रमों, जैसे ऑपरेशन फ्लड (डेयरी, श्वेत क्रांति), पीली क्रांति (तिलहन), और नीली क्रांति (मत्स्य पालन) का शुभारंभ देखा गया, जिसने विविधता लाने में मदद की भारत का कृषि उत्पादन।

बाजार सुधार: 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण कृषि नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। निर्यात बाधाओं को हटा दिया गया था, और किसानों को वैश्विक बाजार के लिए नकदी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसने नए अवसर खोले लेकिन किसानों को वैश्विक मूल्य अस्थिरता से भी अवगत कराया।

प्रौद्योगिकी का उदय: जैव प्रौद्योगिकी के प्रचार और बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों और कृषि आदानों के उपयोग के साथ प्रौद्योगिकी पर जोर जारी रहा। हाल के सुधार (2010-वर्तमान): स्थिरता और किसान कल्याण की ओर हाल के दशकों में, कृषि सुधारों का ध्यान किसानों के लिए इस क्षेत्र को अधिक टिकाऊ, लचीला और लाभदायक बनाने पर रहा है।

किसान कल्याण योजनाएं: सरकार ने किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सिंचाई प्रदान करने के लिए), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (फसल बीमा), और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (आय समर्थन)।

जैविक खेती और मृदा स्वास्थ्य: परमपरागट कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने के लिए उन्हें अपनी मिट्टी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एक धक्का दिया गया है।

डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचा: प्रभावी योजना और नीति-निर्माण के लिए एक फेडरेटेड डेटाबेस बनाने के लिए एग्रीस्टैक जैसी पहल शुरू की गई है। सरकार ने गोदामों और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं सहित बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। द जर्नी सो फार: की आउटकम पिछले 78 वर्षों में, भारत के कृषि सुधारों के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है:

खाद्य घाटे से लेकर खाद्य अधिशेष तक: भारत अब दूध, दालें, मसाले, फल और सब्जियों सहित कृषि वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।

बढ़ी हुई उत्पादकता: फसल उत्पादन और उत्पादकता में कई गुना वृद्धि देखी गई है, जिससे बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

आर्थिक योगदान: कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, जो आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को आजीविका प्रदान करता है और देश के निर्यात में योगदान देता है। जबकि जलवायु परिवर्तन, छोटे लैंडहोल्डिंग, और बेहतर बाजार संबंधों की आवश्यकता जैसी चुनौतियां बनी रहती हैं, स्वतंत्रता के बाद से भारत के कृषि सुधारों की यात्रा एक आत्मनिर्भर और खाद्य-सुरक्षित राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है।

ईवीएम से चुनाव आयोग तक

वीरेन्द्र सिंह परिहार

यह तो पूरे देश को पता है कि वर्ष 2014 से जब से भाजपा केन्द्र की सत्ता में आई तभी से कांग्रेस समेत अधिकांश विपक्षी दल ईवीएम के विरूद्ध युद्ध स्तर पर अभियान चलाते रहे। यह आरोप लगाते रहे कि ईवीएम में हेर-फेर के चलते भाजपा सिर्फ केन्द्र में ही नहीं, अधिकांश राज्यों में भी सत्ता में आ रही है। यद्यपि इस सम्बन्ध में कई बार चुनाव आयोग द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि ऐसा होना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग द्वारा प्रेजेन्टेशन भी दिया गया और उसमें विपक्षी दल के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया ताकि उनके आरोप का परीक्षण हो सके लेकिन उक्त वक्त विपक्षी दलों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। मामला स्पष्ट था कि विपक्षी दलों को भी पता था कि आरोप झूठे हैं पर माहौल बनाने के लिये कि हम हारते नहीं, हराये जाते हैं- इसका औचित्य बताने के लिये ऐसा प्रचारित किया गया।

विपक्ष का कहना था कि ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, यानी वह हवाई जहाज के युग से देश को बैलगाड़ी युग में वापस ले जाना चाहते थे। वह चाहते थे कि जैसे पहले बूथ लूटे जाते थे, एक ही व्यक्ति सैकड़ों बैलेट पर ठप्पा लगा देता था, उस दौर की फिर से शुरूआत हो। इसके लिये विपक्षी दल न्यायालय भी गये पर उन्हें वहाँ भी मुँह की खानी पड़ी। बहुत दिन तक जब यह नैरेटिव नहीं चल पाया और उसकी हवा निकल गई तो राहुल गाँधी समेत पूरे विपक्ष ने चुनाव आयोग पर ही हमला शुरू कर दिया और उस पर वोटो की चोरी कराकर भाजपा को जिताने के आरोप लगाने शुरू कर दिये। इसके पूर्व बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का अभियान का भारी विरोध हुआ। कुछ ऐसा जैसे कि एसआईआर जैसा अभियान चलाने का चुनाव आयोग को कोई अधिकार ही न हो।

बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर न कर सके, इसके लिये विपक्षी दलों समेत कुछ भाजपा विरोधी नैरेटिव चलाने चाले सर्वोच्च न्यायालय पहुँच गये पर सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के काम पर न तो रोक लगाई और न ही याचिकाकर्ताओं को कोई विशेष राहत ही दी। जहाँ तक इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं की आपत्ति है, उसमें उनका कहना है कि जब चुनाव आयोग आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को नहीं मान रहा है तो दूसरे कागज जो उपलब्ध नहीं है, वह कहाँ से लेकर आयें लेकिन लाख टके की बात यह कि जाति जनगणना के लिये तो कागज मिल सकता है तो इसके लिये क्यों नहीं मिल सकता। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया है कि आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी नागरिकता तय करने के लिये पर्याप्त नहीं है। अभी हाल में ही बाम्बे उच्च न्यायालय का भी एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसमें उसने कहा है कि आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड नागरिकता तय करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

निर्णायक बात यह कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह मान लिया है कि वोट जोड़ना और काटना चुनाव आयोग का काम है। जो लोग यह कह रहे हैं कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का नहीं, गृह मंत्रालय का काम है तो क्या वह चाहते हैं कि कोई भारत का नागरिक भले ही न हो, उसे भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। आखिर में चुनाव आयोग वोटर का नाम जोड़ने या काटने में एक ही मुख्य मापदण्ड लिया है कि वह व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय तो यह भी कह रहा है कि पहले मतदाता सूची के लिये 7 दस्तावेज ही देखे जाते थे. बिहार में चुनाव आयोग 11 दस्तावेजों का परीक्षण कर इसे ज्यादा समावेशी बना रहा है।

अब जब बिहार में चुनाव आयोग ने जुलाई के अंत में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से 65 लाख करीब नाम काट दिये हैं। इसमें मृत वोटरों की संख्या 22 लाख, बिहार के बाहर जो मतदाता लम्बे समय से चले गये हैं, उनकी संख्या 36 लाख और जिन मतदाताओं के नाम दो जगह पर हैं, उनकी संख्या करीब 7 लाख है। कुल मिलाकर बिहार में इसके बाद मतदाताओं की संख्या 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ रह गई है। चुनाव आयोग का कहना है, एक भी सही मतदाता छूटे ना, एक भी फर्जी मतदाता जुड़े ना लेकिन फर्जी वोटो के सहारे जो चुनाव जीतने की आस लगाये बैठे थे तो वह तो विधवा-विलाप करेंगे ही। गौर करने की बात यह है कि जहाँ पर विपक्षी दल आधार के आधार पर वोटर लिस्ट बनाये जाने की बातें कर रहे हैं, वहाँ बिहार के सीमांचल में किशनगंज में 68.1 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं लेकिन आधार 126 प्रतिशत बने हुये हैं। कटिहार में मुस्लिम मतदाता 44.12, अररिया में 43.27 और पूर्णिया में 38 प्रतिशत हैं लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में 100 लोगो पर पर 123 प्रतिशत कवरेज है जबकि पूरे बिहार में यह आधार कवरेज 94 प्रतिशत है। इससे यह समझा जा सकता है कि यदि आधार के सहारे मतदाता सूचियाँ बनाई गई तो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा होगा।

राजद, कांग्रेस कमेत विपक्षी दल एसआईआर को एक षड्यंत्र बता रहे हैं, जिसका उद्देश्य गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनना है। इसे वह बैकडोर एनआरसी बता रहे हैं, जो एक दिन पूरे देश में लागू की जायेगी जबकि असलियत में यह बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंयाओं की घुसपैठ एवं अन्य फर्जी मतदाताओं को बाहर करने का मामला है।

अब एक तरफ तो राहुल गाँधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ही पते पर कई वोटर्स, डुप्लीकेट और फेक वोटर हैं। कई के मकान नम्बर 0 है। वह तो यहाँ तक कहते हैं कि मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। यदि राहुल गाँधी की बाते आंशिक रूप से भी सच है तो फिर देश में मतदाता सूचियों को गहन परीक्षण की जरूरत है। यह बात और है कि जब चुनाव आयोग राहुल गाँधी से इस सम्बन्ध में शपथ-पत्र माँगता है तो वह शपथ-पत्र पर अपने आरोप लगाने को तैयार नहीं क्योंकि शपथ-पत्र झूठा होने पर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। संसद को कई दिनों से बाधित कर रखा है और तमाम उल्टे सीधे आरोप लगा रहा है पर शपथ-पत्र पर अपनी बात कहने को तैयार नहीं। इसी से समझा जा सकता है कि मुद्दा विहीन विपक्ष ने ईवीएम के बाद यह दूसरा प्रयोग गढ़ा है।

सबको मिले निशुल्क उपचार और पढ़ने का मौका

राजेश जैन

आज़ादी के समय देश के संविधान-निर्माताओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य को हर नागरिक का मूल अधिकार माना। लेकिन नीतियों के बदलाव और बाज़ार के बढ़ते दखल ने इस सोच को धुंधला कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का हालिया बयान इस मुद्दे को फिर चर्चा में ले आया है कि शिक्षा और चिकित्सा अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा-स्वास्थ्य ऐसा निवेश है जो भारत को एक साथ समृद्धि, समानता और स्थिरता की राह पर ले जा सकता है।

हमारे संविधान-निर्माताओं ने सपना देखा था कि आजाद भारत का हर नागरिक स्वस्थ और शिक्षित होगा। तय हुआ कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर हमें गरीबी, अशिक्षा और बीमारी के चक्रव्यूह से निकलना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को हर नागरिक तक निःशुल्क और समान रूप से पहुंचना होगा। लेकिन पिछले आठ दशक में, इस सोच की जगह धीरे-धीरे बाज़ार-आधारित नीतियों ने ले ली। सरकारी संस्थान, जिन्हें मज़बूती से खड़ा होना चाहिए था, उन्हें उपेक्षित छोड़ दिया गया। निजी क्षेत्र के लिए दरवाज़े इस तरह खोले गए कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा धीरे-धीरे सबसे महंगे कारोबारों में बदल गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का हालिया बयान इस विषय को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ले आया है। उन्होंने इसी सप्ताह के शुरू में इंदौर में साफ कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। स्कूल और अस्पताल, जो पहले सेवा और समाज-निर्माण के प्रतीक थे, अब मुनाफाखोरी के केंद्र बन गए हैं। आज हालत यह है कि एक मध्यमवर्गीय पिता अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या अपनी बीमारी के इलाज के लिए घर गिरवी रखने या बेचने तक को मजबूर हो जाता है। यह विडंबना ही है कि जिन दो चीज़ों से इंसान का जीवन संवर सकता है—शिक्षा और स्वास्थ्य—वे ही उसकी सबसे बड़ी आर्थिक मुसीबत बन चुकी हैं। अस्पताल और स्कूल की संख्या तो बढ़ रही है, नए भवन, आधुनिक मशीनें और एयर-कंडीशन कैंपस भी दिखते हैं, लेकिन उनकी फीस और खर्च इतने ज्यादा हैं कि आम आदमी वहां कदम रखने से पहले सौ बार सोचता है।

इसलिए जरूरी है

अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य को निःशुल्क कर दें, तो इसके लाभ केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी क्रांतिकारी होंगे। सबसे बड़ा फायदा होगा गरीबी पर सीधा प्रहार। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल लगभग 6 करोड़ लोग केवल इलाज के खर्च के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। अगर स्वास्थ्य सेवा मुफ्त हो जाए तो यह सिलसिला लगभग खत्म हो सकता है। शिक्षा के मामले में भी यही सच है। महंगी फीस के कारण लाखों प्रतिभाशाली छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। मुफ्त शिक्षा से यह प्रतिभा व्यर्थ नहीं जाएगी बल्कि देश के विकास में लगेगी।

यह कदम समाज में समान अवसर सुनिश्चित करेगा। अभी एक अमीर परिवार का बच्चा बेहतरीन स्कूल और हॉस्पिटल का लाभ ले सकता है जबकि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में टूटी बेंच पर बैठकर पढ़ता है और बीमार पड़ने पर सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन में खड़ा होता है। मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं इस खाई को पाटेंगी। यह केवल नैतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है—क्योंकि एक समान अवसर वाला समाज अधिक स्थिर और प्रगतिशील होता है।

एक स्वस्थ और शिक्षित जनसंख्या देश के मानव संसाधन को सबसे बड़ी पूंजी में बदल देती है। 21वीं सदी में, जब ज्ञान और तकनीक ही शक्ति के असली स्रोत हैं तो एक अनपढ़ या बीमार समाज वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगा। आज जापान, दक्षिण कोरिया और फिनलैंड जैसे देश इसलिए आगे हैं क्योंकि उन्होंने दशकों पहले शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी निवेश किया।

यह हैं चुनौतियां

लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले हमें मौजूदा चुनौतियों का सामना करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती है—अत्यधिक व्यावसायीकरण। निजी स्कूलों और अस्पतालों ने सेवा-भाव की जगह मुनाफे को अपना लक्ष्य बना लिया है। शिक्षा के नाम पर हर साल फीस में बेहिसाब बढ़ोतरी होती है। अस्पतालों में मरीज़ से अनावश्यक टेस्ट कराए जाते हैं, महंगे पैकेज बेचे जाते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है—सरकारी निवेश की कमी। भारत में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल करीब 3.1% और स्वास्थ्य पर 2.9% खर्च होता है, जबकि विश्व औसत 4% से अधिक है और विकसित देशों में यह 6-10% है।

इस बदलाव के भावनात्मक प्रभाव को समझने के लिए केवल एक दृश्य सोचिए—एक गांव की 12 साल की बच्ची, जो अभी खेतों में मजदूरी करती है अगर उसे मुफ्त और अच्छी शिक्षा मिले, तो वह कल एक इंजीनियर या डॉक्टर बन सकती है। एक गरीब किसान, जो बीमारी में अपने खेत बेच देता है, अगर उसे मुफ्त इलाज मिले, तो वह अपना जीवनयापन जारी रख सकता है। ऐसे लाखों जीवन एक नीति से बदल सकते हैं।

हमारे पास दुनिया के उदाहरण भी हैं। फिनलैंड ने पूरी तरह मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देकर अपने समाज को सबसे प्रतिस्पर्धी बनाया है। क्यूबा ने 100% मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देकर डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कनाडा में टैक्स से वित्तपोषित यूनिवर्सल हेल्थकेयर ने हर नागरिक को समान चिकित्सा सुविधा दी है। इन देशों का मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च नहीं, बल्कि सबसे बड़ा निवेश हैं, जो भविष्य में कई गुना लाभ देता है।

ऐसे संभव है बदलाव

इस स्थिति को बदलने के लिए एक स्पष्ट, साहसिक और व्यावहारिक रोडमैप चाहिए। सबसे पहले, सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 6% तक बढ़ाने का कानूनी प्रावधान करना चाहिए। राज्यों को प्रदर्शन के आधार पर फंड देना चाहिए ताकि बेहतर परिणाम देने वालों को प्रोत्साहन मिले। निःशुल्क व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है—पहले प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह मुफ्त किया जाए फिर 5 वर्षों में इसे उच्च शिक्षा और विशेष चिकित्सा तक बढ़ाया जाए।

निजी क्षेत्र को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए एक राष्ट्रीय शुल्क एवं दर आयोग बनाया जा सकता है जो स्कूलों और अस्पतालों की फीस और इलाज के खर्च की अधिकतम सीमा तय करे। सेवा-भाव से काम करने वाले संस्थानों को कर-छूट और सरकारी मदद दी जाए, जबकि मुनाफाखोरी करने वालों के लाइसेंस रद्द हों और उन पर भारी जुर्माना लगे। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए—हर अनुबंध, फंड और टेंडर की जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर डाली जाए और शिकायत-निवारण के लिए स्वतंत्र संस्था बनाई जाए।

भारत के लिए भी आर्थिक मॉडल तैयार किया जा सकता है। लक्ज़री टैक्स, प्रदूषण टैक्स और तंबाकू-शराब जैसे उत्पादों पर सिन टैक्स से प्राप्त राशि को पूरी तरह शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कम से कम आधा बजट इन दो क्षेत्रों के लिए अनिवार्य किया जाए। प्रवासी भारतीयों के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ डेवलपमेंट बॉन्ड जारी किए जाएं, ताकि वे अपने देश के विकास में योगदान दे सकें।

तकनीक इस बदलाव को तेज़ और सस्ता बना सकती है। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए दूरदराज के इलाकों तक सेवाएं पहुंच सकती हैं। डिजिटल हेल्थ कार्ड से मरीज का मेडिकल हिस्ट्री हर अस्पताल में तुरंत उपलब्ध होगा, जिससे इलाज तेज़ और सस्ता होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शिक्षा सामग्री और डायग्नोसिस टूल तैयार किए जा सकते हैं जिससे गुणवत्ता में सुधार होगा।

देश-दुनिया को मोदी का स्पष्ट और सख्त संदेश

राजेश कुमार पासी

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार हर साल ये देश करता है क्योंकि इस मौके पर प्रधानमंत्री देश को विशेष संदेश देते हैं। इस बार इस संबोधन का इंतजार कुछ ज्यादा था क्योंकि देश घरेलू और बाहरी मोर्चे पर कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। मेरा मानना है कि मोदी के कार्यकाल में देश के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां पहले कभी नहीं आई थी। मोदी जी ने जिस दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ इन चुनौतियों को स्वीकार किया है, उससे लगता है कि वो जानते हैं इन घरेलू और बाहरी चुनौतियों का सामना कैसे करना है। वो यह भी जानते हैं कि देश को वो इन चुनौतियों से पार ले जाएंगे।

दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को खुली धमकियां दे रहे हैं लेकिन मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा कर दी कि वो देश के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों के लिए दीवार बन कर खड़े हैं। उन्होंने न केवल भारत के सामने खड़ी चुनौतियों का जिक्र किया बल्कि स्पष्ट रूप से बताया कि वो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या करने वाले हैं। एक तरफ उन्होंने देश के दुश्मनों को जवाब दिया तो दूसरी तरफ देश की जनता को आश्वासन दिया कि देश मजबूती से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने एक तरह से देश और दुनिया के भारत विरोधियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। यही कारण है कि उन्होंने न केवल पाकिस्तान और अमेरिका को संदेश दिया बल्कि नक्सलवादियों, घुसपैठियों और आतंकवादियों को भी चुनौती दे दी। उनकी बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त थी और वो गजब आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरे हुए दिखाई दिए।

मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि भारत के लिए अब आत्मनिर्भर बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होते तो ऑपरेशन सिंदूर इतना सफल नहीं हो सकता था। देखा जाए तो भारत की जनसंख्या को देखते हुए कोई भी देश भारत की मांग पूरी नहीं कर सकता। अगर हम अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर रहे तो हमारा शोषण होता रहेगा क्योंकि दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाले देशों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन बनाने की बात कही और इस साल के अंत तक भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में आने की बाद कही। उन्होंने अमेरिका और चीन को संदेश दे दिया कि इस मामले में भारत आप पर निर्भर नहीं रहेगा। उन्होंने कर प्रणाली में बड़े सुधार कर जनता को दिवाली तक टैक्स के बोझ से राहत देने की बात कही है। इस साल भारत सरकार आयकर में पहले ही जनता को बड़ी राहत दे चुकी है। इससे भारत सरकार देश में विनिर्माण और निर्यात को बढ़ाना चाहती है। इस घोषणा के बाद ही भारत सरकार ने जीएसटी की दरों में संशोधनों से जुड़ा प्रस्ताव राज्यों को भेज दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार जीएसटी की अब चार की जगह सिर्फ दो दरें 5 और 18 प्रतिशत की ही होंगी। उन्होंने एक बात कही है कि संकटों के सामने हम रोयेंगे नहीं और न ही किसी की लाइन छोटी करेंगे बल्कि हम अपनी बड़ी लाइन खीचेंगे। इसलिए उन्होंने डॉलर को कमजोर करने की जगह अपनी रुपये को मजबूत करने की बात कही।

उन्होंने अपना फाइटर जेट बनाने की बात भी कही। इसके अलावा निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वालों को पन्द्रह हजार की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर दिलाने के लिए करीब एक लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। देश की आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करते हुए मोदी जी ने फार्मा उद्योग को भी नवाचार का पाठ पढ़ाया। उन्होंने याद दिलाया कि कोविड काल में आपदा को अवसर बनाते हुए भारत ने मानव जाति का कल्याण किया। आत्मनिर्भर भारत के व्यापक विजन में उन्होंने उर्वरक उत्पादन को तरजीह देते हुए कहा कि देश अब दूसरे देशों पर आश्रित नहीं रहेगा। रक्षा एवं ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबन के प्रयासों की तरह ही खाद्य सुरक्षा के लिए उर्वरक में भी आत्मनिर्भरता जरूरी है। अमेरिका भारत को लगातार टैरिफ वॉर से डराने की कोशिश कर रहा है लेकिन मोदी जी ने लाल किले से बता दिया कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने के कारण भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है लेकिन सच्चाई यह है कि वो भारत के कृषि, मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग में अपनी कंपनियों की एंट्री चाहता है। उन्होंने बिना अमेरिका का नाम लिए उसे संदेश दे दिया कि भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने देश में मौजूद इस वर्ग और अमेरिका को बता दिया है कि कोई भी शक्ति उनसे इन समुदायों के लिए अहितकारी फैसले नहीं करवा सकती। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो व्यक्तिगत रुप से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। वास्तव में अमेरिका अपनी बड़ी कंपनियों को लाकर भारत के कृषि, मत्स्य पालन और डेयरी क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। इससे शुरू में अमेरिका अपने बेहद सस्ते उत्पाद देगा ताकि इन क्षेत्रों में कब्जा किया जा सके फिर बाद में कई गुना कीमत बढ़ाकर भारतीय जनता का शोषण करेगा।

पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते क्योंकि पाकिस्तानी नेता पिछले कई दिनों से भारत को पानी रोकने पर युद्ध की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को भी संदेश दे दिया कि वो पाकिस्तान को न भड़काए क्योंकि आजकल पाकिस्तान अमेरिका की गोद में ही बैठा हुआ है और वहीं से बैठकर भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका को बता दिया कि भारत अब परमाणु बम की धमकी से ब्लैकमेल नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने संदेश दे दिया कि भारत नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट में कोई अंतर नहीं करेगा। इससे स्पष्ट है कि भारत आतंकवादी हमले पर पाकिस्तान को बड़ा जवाब दे सकता है।

मोदी जी के संबोधन से स्पष्ट हो गया है कि वो सुरक्षा के बिना विकास को महत्व नहीं देते हैं इसलिए उन्होंने आतंकवादियों, नक्सलवादियों और घुसपैठियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। पहली बार उन्होंने कहा कि भारत की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने घुसपैठियों को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया और कहा कि ये लोग हमारे युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये लोग हमारी बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये समय घुसपैठियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सबसे बढ़िया है क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देश भी घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान ने भी अफगानियों को अपने देश से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीमावर्ती राज्यों की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश को नाकामयाब बनाने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही। वास्तव में घुसपैठियों के कारण बंगाल, झारखंड, बिहार, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है जिससे देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने के बारे में भी देश को कहा कि अब नक्सलवाद को कुछ इलाकों तक सीमित कर दिया गया है और देश से उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।

उन्होंने देश के महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र मिशन शुरू करने की घोषणा की। इसमें दुश्मन को निर्णायक जवाब देने के लिए स्वदेशी रक्षा कवच विकसित करने की बात है। उन्होंने कहा कि देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को नए प्लेटफार्म से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह हथियार प्रणाली न केवल दुश्मन के हमले को बेअसर करेगी बल्कि दुश्मन पर कई गुना अधिक वार करेगी। उन्होंने कहा कि जो भी टेक्नोलोजी हम पर आक्रमण करे, हमारी टेक्नोलोजी उससे बेहतर होनी चाहिए। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के लंबे संबोधन का सार यही है कि भारत को हर हाल में आत्मनिर्भर बनना होगा, इसके अलावा भारत के पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने इसके लिए भारत को जनता का साथ मांगा है।

अलास्का से उठा सवाल: क्या भारत बनेगा शांति का सेतु?

[शांति की पुकार: असफल वार्ता के बाद भारत का बढ़ता महत्व]

जब विश्व की निगाहें अलास्का के एंकोरेज पर टिकी थीं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात रूस-यूक्रेन युद्ध की आग को शांत करने की उम्मीद जगा रही थी, तब भारत सहित पूरी दुनिया सांस थामे इस ऐतिहासिक क्षण की प्रतीक्षा में थी। यह मुलाकात, जो वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही थी, तीन घंटे की गहन चर्चा के बाद बेनतीजा रही। ट्रंप का दृढ़ कथन, "समझौता तभी, जब वास्तव में समझौता हो," और पुतिन का युद्ध के "मूल कारणों" को समाप्त करने पर जोर, वैश्विक कूटनीति की जटिलता को उजागर करता है। भारत, जो शांति का सिपाही और रणनीतिक संतुलन का प्रतीक रहा है, इस विफलता को एक चुनौती के साथ-साथ अवसर के रूप में देखता है।

रूस-यूक्रेन युद्ध, जो फरवरी 2022 से शुरू होकर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को हिलाकर रख चुका है, भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। इस युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया, तेल और गैस की कीमतों में उछाल लाया और खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव डाला। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है, ने इस संकट का सामना करने के लिए रूस से रियायती तेल आयात को बढ़ाया। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहा, लेकिन वैश्विक बाजारों की अस्थिरता ने नई चुनौतियां खड़ी कीं। इसके साथ ही, भारत ने क्वाड और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में पश्चिमी देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को गहरा किया है, जिसने उसे एक नाजुक संतुलन की राह पर ला खड़ा किया है।

इस संदर्भ में, अलास्का की असफल वार्ता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह विफलता भारत को अपनी कूटनीति को और तीक्ष्ण करने और वैश्विक मंच पर अपनी तटस्थता को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन, "यह युद्ध का युग नहीं है," भारत की शांति-समर्थक नीति को रेखांकित करता है। यह नीति भारत को रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का अवसर देती है, जिससे वह वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान दे सकता है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की इस वार्ता में अनुपस्थिति ने यूरोप में चिंताओं को बढ़ा दिया। जेलेंस्की ने रूसी हमलों की निरंतरता पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जो मॉस्को की युद्ध समाप्त करने की अनिच्छा को दर्शाता है। दूसरी ओर, पुतिन ने युद्ध के "मूल कारणों" पर जोर दिया, जो नाटो के विस्तार और रूस की सुरक्षा चिंताओं से जुड़े हैं। यह रूस की अडिग स्थिति को दर्शाता है। वहीं, ट्रंप की सख्त शर्तें, जो युद्ध के त्वरित अंत की संभावनाओं को धूमिल करती हैं, वैश्विक कूटनीति की जटिलता को और स्पष्ट करती हैं।

इस स्थिति में भारत की तटस्थता एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। भारत ने रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखा है, जबकि यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करके अपनी शांति-समर्थक छवि को मजबूत किया है। 2022 से, भारत ने यूक्रेन को दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की है, जो उसकी मानवीय नीति का प्रमाण है। यह तटस्थता भारत को एक ऐसे मध्यस्थ के रूप में स्थापित करती है, जो न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए एक सेतु का निर्माण भी कर सकता है।

अलास्का की यह असफल वार्ता भारत के लिए अपनी कूटनीतिक भूमिका को और सक्रिय करने का एक सुनहरा अवसर है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर शांति प्रस्तावों का समर्थन किया है और रूस-यूक्रेन के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया है। भारत की अद्वितीय स्थिति न तो पूरी तरह पश्चिमी ब्लॉक का हिस्सा, न ही रूस-चीन गठजोड़ का, उसे वैश्विक मंच पर एक विश्वसनीय मध्यस्थ बनने का अवसर देती है। यह स्थिति भारत को वैश्विक शांति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है।

इसके साथ ही, युद्ध के लंबा खिंचने की संभावना भारत को अपनी ऊर्जा और रक्षा नीतियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। भारत ने हाल के वर्षों में स्वदेशी रक्षा उत्पादन और ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए, 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत भारत ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों और तकनीकों का विकास तेज किया है। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ाकर भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। यह अनिश्चितता का दौर भारत के लिए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को और सशक्त करने का अवसर है।

अलास्का की यह नाकाम वार्ता वैश्विक कूटनीति की नाजुकता को उजागर करती है। यह दिखाती है कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए केवल बड़े नेताओं की मुलाकातें पर्याप्त नहीं हैं; इसके लिए गहन संवाद, आपसी विश्वास और रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत, जो अपनी कूटनीतिक चतुराई और तटस्थता के लिए जाना जाता है, इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत की संवाद और सहयोग की नीति उसकी वैश्विक साख को मजबूत करती है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत को शांति प्रस्तावों को और जोरदार तरीके से उठाना होगा। साथ ही, भारत को अपने आर्थिक और रक्षा हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक स्वायत्तता को और सशक्त करना होगा।

भारत की यह तटस्थता और कूटनीतिक चतुराई उसे वैश्विक शांति में योगदान देने का अवसर देती है। भारत ने पहले भी कई मौकों पर वैश्विक संकटों में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, और यह स्थिति भी उसकी कूटनीतिक क्षमता को परखने का अवसर है। भारत को चाहिए कि वह न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे, बल्कि वैश्विक मंच पर एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरे, जो स्थिरता और शांति की नई राह बनाए।

अलास्का की असफल वार्ता ने वैश्विक कूटनीति की जटिलताओं को उजागर किया है, लेकिन भारत के लिए यह एक अवसर है। अपनी तटस्थता, कूटनीतिक चतुराई और रणनीतिक स्वायत्तता के बल पर भारत न केवल अपने हितों की रक्षा कर सकता है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यह समय भारत के लिए अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत करने का है। रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे संकटों के बीच भारत की नीति—संवाद, सहयोग और आत्मनिर्भरता—उसे एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित करती है, जो न केवल अपने भविष्य को सुरक्षित करे, बल्कि विश्व को शांति और समृद्धि की ओर ले जाए।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

ताकि किश्तवाड़ और धराली जैसी आपदाओं से बचा जा सके !

दिन-ब-दिन प्रकृति मानव को अपना रौद्र रूप दिखा रही है। भूस्खलन हो, भू- धंसाव हो, बाढ़ हो(अतिवृष्टि), बादल फटना हो, अनावृष्टि हो(सूखा), भूकंप हो या सुनामी सब कहीं न कहीं, कोई माने या नहीं मानें, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय गतिविधियों से ही जुड़े हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि बादल फटने की घटनाएँ अब केवल प्राकृतिक आपदाएँ भर नहीं रहीं, बल्कि इनमें मानवीय लापरवाहियों और अवैज्ञानिक विकास कार्यों की भी बड़ी भूमिका है।सच तो यह है कि ऐसी घटनाएं मानव जनित संकट हैं। आज के समय में जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ बढ़ी हैं। पहाड़ी ढलानों पर अचानक अत्यधिक पानी गिरने से वहां की मिट्टी ढीली हो जाती है और लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ जाता है। मानवीय गतिविधियों या कारणों की बात करें, तो कहना ग़लत नहीं होगा कि आज के समय में अनियंत्रित निर्माण कार्य प्राकृतिक आपदाएं जन्म ले रहीं हैं। आज नदियों और ढलानों पर घर, होटल, सड़कें बनाने से जलधाराओं के प्राकृतिक मार्ग मानव ने बाधित कर दिए हैं। सच तो यह है कि मानव हद से ज्यादा स्वार्थी और लालची होता चला जा रहा है।वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है और जंगलों के घटने से पानी रोकने की क्षमता खत्म हो गई है। पर्यटन का दबाव भी है। हर साल लाखों की संख्या में आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक स्थानीय पारिस्थितिकी पर बोझ(वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण) डालते हैं। यह बहुत ही दुखद है कि आज संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की ईमानदारी और पूर्ण इच्छाशक्ति के पूर्व तैयारियां नहीं की जातीं। अक्सर यह देखा गया है कि विभिन्न तीर्थयात्राओं व मेलों के दौरान भीड़ नियंत्रित करने और सुरक्षित मार्ग बनाने की अनदेखी होती है। आज सड़कें, घर और होटल और विभिन्न निर्माण कार्य बिना भू-वैज्ञानिक अध्ययन किए ही निर्माण कर लिए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अतिक्रमण किया जाता है। ग्रीन टूरिज्म की ओर हमारा ध्यान कम ही होता है और इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। हाल ही में हमने देखा कि उत्तरकाशी के धराली में जान-माल को बहुत क्षति पहुंची। हमने देखा कि धराली में बीते पांच अगस्त को खीरगंगा से आई बाढ़ ने मिनटों में बाज़ार, होटल और घर बहा दिए।कई लोग असमय काल के ग्रास बन गए।आंकड़े बताते हैं कि (विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक) धराली क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। धराली में बादल फटने से हुई तबाही से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती-पड्डर(नियंत्रण रेखा के पास स्थित गांव) में भी ठीक वैसा ही हादसा हो

गया। बादल फटने से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। अचानक आए सैलाब में साठ से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और सैकड़ों लोग लापता हो गए। जानकारी के अनुसार यह बादल चशोती में फटा, जो मचैल माता मंदिर के मार्ग पर स्थित है। यह आखिरी गांव है, जहां किसी गाड़ी से पहुंचा जा सकता है। खबरों में आया है कि हादसे के समय मचैल माता की यात्रा चल रही थी, जिसकी वजह से रूट पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। घटना के बाद मंदिर की वार्षिक यात्रा को स्थगित कर दिया गया और रेस्क्यू अभियान चलाए गए। वास्तव में उत्तरकाशी और किश्तवाड़ में हुईं प्राकृतिक आपदाएं मानव के लिए एक बड़ा सबक है।चशोती गांव गांव पड्डर घाटी में पड़ता है और यहां अठारह सौ से लेकर करीब चार हजार मीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं। जब भी यहां बारिश होती है तो पानी पहाड़ों से होते हुए बहुत ही तीव्र गति से नीचे आता है। स्थानीय प्रशासन को इस बात की जानकारी भी है, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन द्वारा आपदा बचाव की तैयारियां नहीं की गईं ,यह वास्तव में बहुत ही दुखद है। इन दिनों पूरे भारत में जोरदार बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग व प्रशासन को बारिश व किसी भी आपदा के लिए पूर्व में ही माकूल इंतजाम करने चाहिए और सदैव तैयार रहना चाहिए। हालांकि, यह भी नहीं है कि आपदा प्रबंधन विभाग, स्थानीय प्रशासन और सरकारें आपदाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठातीं हैं, लेकिन समय रहते यदि पूर्ण ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सजगता और सतर्कता बरतकर निर्णय ले लिए जाएं तो बहुत हद तक जान-माल का नुक़सान कम तो किया ही जा सकता है लेकिन सभी तभी चेतते हैं,जब ऐसे हादसे घटित हो जाते हैं,यह बहुत ही दुखद है। गौरतलब है कि साढ़े नौ हजार फुट ऊंचाई पर स्थित मचैल माता मंदिर जाने के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहां यक्ष प्रश्न यह उठता है कि स्थानीय प्रशासन ने यहां लंगर और दुकानें लगाने की अनुमति आखिर क्यों दी, यह जानते हुए भी कि जम्मू-कश्मीर में बादल फटने की घटनाएं हर वर्ष बढ़ रही हैं।इधर, हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश थम नहीं रही है। राज्य के कुल्लू जिले में दो अलग-अलग जगह से बादल फटने की खबरें आई हैं। जानकारी के अनुसार कुल्लू के बंजार और आनी निरमंड सब डिवीजन के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ये घटनाएं हुई हैं।बादल फटने से तीर्थन घाटी और आसपास के कई निचले ग्रामीण इलाकों में पानी और मलबा भर गया। हालांकि, प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई गांवों को खाली करा लिया, लेकिन पहाड़ी इलाकों विशेषकर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में इस तरह की घटनाओं से अब सजग होने और इससे निपटने की जरूरत है।यह बात ठीक है कि कुदरत के कहर जैसे कि बाढ़, भूकंप, बादल फटना, भूस्खलन, जंगल की आग, सूखा आदि को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन इंसान सतर्कता, तैयारी और सही जीवनशैली से इसका असर ज़रूर कम कर सकता है। वास्तव में कुदरत अगर अपना क्रोध प्रकट कर रही है, तो इसे समझने और चेतने का समय है। हमें यह बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि कुदरत के कहर से बचना केवल सरकार की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर हम पर्यावरण का सम्मान करें और सावधानी और सतर्कता अपनाएँ, तो बड़े हादसों को काफी हद तक टाला जा सकता है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार,

ओड़िसा मे गुंडा एक्ट लागू करने की योजना बना रही है

मनोरंजन सासमल , वरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : राज्य सरकार अपराधियों को दंडित करने के लिए गुंडा एक्ट लागू करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लेकिन असामाजिक तत्व इसका पालन नहीं कर रहे हैं। कानून-व्यवस्था की स्थिति बार-बार बिगड़ रही है। जैसे-जैसे पूजा नजदीक आ रही है, अपराधी और सक्रिय हो गए हैं।बंदर की मूर्ति के लिए मिट्टी तैयार हो चुकी है। पूजा आयोजन समिति ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। लेकिन पूजा से पहले ही अवैध वसूली करने वाले सक्रिय हो गए हैं। बंदरगाह शहर पारादीप से भी ऐसी ही एक गंभीर शिकायत आई है। जहाँ एक असहाय वृद्ध महिला से 5,000 रुपये का पूजा चंदा माँगा जा रहा है। इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताने पर वृद्ध महिला पर अत्याचार होने के बाद हड़कंप मच गया है। स्थानीय व्यापारी पुलिस थाने में जमा हो गए हैं। सिर्फ़ चंदा लेने वाले ही नहीं, पूजा के दौरान इस माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। चूँकि लोग उत्सव के मूड में हैं, इसलिए अच्छी कमाई की उम्मीद में वे अपना जाल बिछा रहे हैं। इस माफिया ओडिशा से लेकर कोलकाता, बिहार और बांग्लादेश तक फैल चुका है। नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए एसटीएफ की छापेमारी जारी है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ ज़ब्त किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जताई है। ज़रूरत पड़ने पर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री की चिंता के बावजूद, कुछ जगहों पर अपराधी बेपरवाह हो गए हैं। हर दिन राज्य के अलग-अलग हिस्सों से अपराध की खबरें आ रही हैं। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। जवाब में, कानून मंत्री ने कहा कि राज्य में अपराध रोकने के लिए काम चल रहा है। अपराध करने वालों को १४ से 48 घंटों के भीतर गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार भविष्य में और सख्त होगी। इस बीच, मंत्री और पारादीप विधायक संपदा स्वैन ने चंदा वसूली की निंदा की है। राज्य जहाँ कानून-व्यवस्था की स्थिति से जूझ रहा है, वहीं पूजा के दौरान अपराध को नियंत्रित करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है।

कोरेमुला स्थित श्री आई माता मंदिर में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में श्री आईमाता जी भजन मंडली की ओर से ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए। अवसर पर उपस्थित संरक्षक प्रभुराम परिहारिया, अध्यक्ष कालुराम काग, सचिव डायाराम लचेटा, राजाराम गेहलोत, राजाराम पंवार, प्रकाश खंडाला, ताराराम परिहारिया, रामलाल राठौड़, बाबूलाल परिहार ,पुनाराम हाम्बड़, देवाराम परिहार,कमल किशोर एवं समाजबंधु ।

बालाजी नगर स्थित श्री आईजी गौशाला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर्ष उल्लास के साथ मनायी गयी। पंडित गोविंद शर्मा व मंगलाराम पंवार द्वारा पूजा-अर्चना कर 56 भोग लगाए गए। आईमाता भजन मण्डली के अचलाराम हाम्बड़ व मोहनलाल भायल एंड पार्टी ने भजन प्रस्तुत किए। अवसर पर गौशाला अध्यक्ष मंगलाराम पंवार, सचिव हुक्माराम सानपुरा, सह सचिव ढगलाराम सेपटा, कोषाध्यक्ष नारायण परिहार, भगाराम मुलेवा, मोतीलाल काग, भंवरलाल मुलेवा, नेमीचंद काग, चन्द्र प्रकाश गेहलोत,हीरालाल चोयल, चेनाराम परिहार, पारसमल शर्मा, किशनलाल पंवार, बाबूलाल मुलेवा, अशोक प्रजापत, जयराम पंवार, गोपाराम मुलेवा, मांगीलाल परिहार, लादुराम सीरवी, ओमप्रकाश परिहार, ओमप्रकाश काग, मोतीलाल राठौड़, अशोक पंवार (माली) महिला मंडल मैना देवी सीरवी, सुगना बाई सीरवी, प्रेमा देवी सानपुरा,पारी बाई सीरवी, नीतू सीरवी, गणकी सीरवी, कमला सीरवी व अन्य उपस्थित थे।

झारखंड के गोड्डा में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से चार लोगों की मौत

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

रांची , झारखंड में दर्दनाक घटना हुई है, गढ़वा जिला मुख्यालय से सटे नवादा गांव में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सेप्टिक टैंक की सेटरिंग खोलने के दौरान हुआ। इस हादसे के दौरान चारों बारी-बारी से एक-दूसरे को देखने टैंक में उतरे थे। शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। मृतकों में नवादा गांव निवासी मोती चौधरी के तीन पुत्र 55 वर्षीय राजू शेखर चौधरी, 50 वर्षीय अजय चौधरी और 42 वर्षीय चंद्रशेखर चौधरी के अलावा गांव के ही मल्टू राम के रूप में हुई है। चारों का पोस्टमार्मट करवाने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

इस मामले के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अजय चौधरी ने नया सेप्टिक टैंक बनवाया है। शुक्रवार को सेटरिंग खोला जा रहा था। सेटरिंग खोलने सबसे पहले मजदूर मल्टू राम टैंक में उतरा। जब वह काफी देर तक सेफ्टिक टैंक से बाहर नहीं आया, तब राजू शेखर चौधरी उसे देखने नीचे उतरे। वह भी नहीं निकला तब अजय चौधरी अंदर गए। फिर चंद्रशेखर चौधरी भी नीचे उतरे। लेकिन, दम घुटने से सभी अंदर ही फंस गए। काफी देर तक जब चारों बाहर नहीं आए, तब अनहोनी की आशंका में ग्रामीणों ने शोर मचाया। उसके बाद ग्रामीणों जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि चारों की मौत दम घुटने से हुई है। इस हादसे की सूचना पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, एसडीपीओ नीरज कुमार, गढ़वा थाना प्रभारी बृज कुमार अस्पताल पहुंचे। इसकी जानकारी लेने के बाद शवों को कब्जे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए एसडीओ ने कहा कि सरकारी प्रावधान के तहत योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

राउरकेला में हत्यारे ने पिता को बेटे की हत्या का केस वापस लेने की धमकी दी

मनोरंजन सासमल , वरिष्ठ पत्रकार

राउरकेला/भुबनेश्वर : केस वापस करो , वरना तुम भी अपने बेटे की तरह मर जाओगे। पहले तो तुमने अपने बेटे की जान ली और जेल गए। लेकिन इस हत्यारे को बस इतना ही यकीन नहीं हुआ। जेल से लौटने के बाद बेटे ने अपने पिता को हत्या का केस वापस लेने की धमकी दी। बदमाश ने सिर पर बंदूक तानकर मृतक के पिता को ऐसी धमकियाँ दीं राउरकेला शहर में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली है। राउरकेला शहर के छेंड वीएसएस मार्केट में 9 अप्रैल को मुकेश कर नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। अब उस हत्याकांड के आरोपी ज़मानत पर बाहर आ गए हैं। ज़मानत पर बाहर आने के बाद, हत्यारों ने एक और कांड कर दिया है। बदमाशों ने युवक के पिता सुधीर कुमार कर को हत्या का मामला वापस

लेने की धमकी दी है। उन्होंने उसके सिर पर बंदूक रखकर केस वापस लेने की धमकी दी। वरना तुम्हें भी तुम्हारे बेटे की तरह मार दिया जाएगा। जिसके बाद मृतक मुकेश के पिता रघुनाथ पाली डरे-सहमे पुलिस थाने पहुँचे हैं। यह घटना अब स्थानीय इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। 9 अप्रैल को हुए इस हत्याकांड में छेंड थाना पुलिस ने लगभग 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में मुकदमा चलाया था। अब, कुछ आरोपियों के ज़मानत पर बाहर आने के बाद, एक और ऐसी ही घटना घटी है। मुकेश की हत्या करने वाले बदमाशों ने धमकी दी है कि हत्या का मामला वापस ले लो वरना वे तुम्हें भी उसी तरह मार देंगे जैसे उन्होंने तुम्हारे बेटे को मारा था। ख़बरों के मुताबिक, ये आरोपी पहले किसी हत्या के मामले में शामिल नहीं थे। कल शाम, जब मृतक मुकेश के पिता सुधीर इयूटी से घर लौट रहे थे, तभी तीन युवकों ने उनके सीने और सिर पर तीन बंदूकें तान दीं और मुकेश की हत्या का केस वापस लेने की धमकी दी। बेटे की हत्या का गम अभी कम भी नहीं हुआ था कि बदमाशों की धमकियों ने परिवार को फिर से परेशान कर दिया है। डर और आशंका के चलते मृतक के पिता और माता दोनों रघुनाथपाली थाने पहुँचे और धमकी देने वाले बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए अपनी सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई।

उप्पल न्यूरो अस्पताल में हड्डियों एवं जोड़ो से जुड़े रोगों के मुफ्त कैंप में 325 से ज्यादा मरीजों ने चेकअप करवाया

अमृतसर 17 अगस्त (साहिल बेरी)

रानी का बाग स्थित उप्पल न्यूरो अस्पताल में आजादी दिवस के उपलक्ष्य पर हड्डियों एवं जोड़ो से संबंधित रोगों की जांच के लिए मुफ्त चैक-अप कैंप लगाया गया कैंप में हड्डियों में कमजोरी का पता लगाने के लिए बी एम डी टेस्ट भी मुफ्त किया गया साथ ही सभी प्रकार की जांचो में भारी छूट भी दी गई

डॉ अशोक उप्पल जानकारी देते हुए बताया की आज कल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में दुर्घटनाये बढ़ रही है ऐसे में हड्डियों की देखभाल करना बहुत जरुरी हो जाता है उन्होंने कहा की आजकल हड्डियों एवं जोड़ो से जुड़े रोगों के इलाज में पहले से भी बहुत ज्यादा प्रगति हुई है जिससे इलाज करना और भी आसान एवं सटीक हो गया है उन्होंने बताया की उप्पल न्यूरो अस्पताल में हड्डी रोगो के माहिर डॉ पर्व ओहरी नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे है

कैंप के दौरान डॉ पर्व ओहरी ने

बताया की पुरे भारत में लगभग 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस यानि हड्डियों , घुटनो एवं जोड़ो के कमजोर हो जाने की बीमारी से जूझ रहे है उनमे से 80 प्रतिशत महिलाये है पर दुःख की बात है की सिर्फ 20 प्रतिशत लोगो का इलाज हो पाता है इसलिए आज मुफ्त कैंप का आयोजन किया गया है

उन्होंने कहा की उप्पल अस्पताल में संपूर्ण रूप से हड्डियों के रोगो का विभाग शुरू हो गया है जिसमे सभी प्रकार की आधुनिक तकनीकों द्वारा जोड़ बदलने के ऑपरेशन, चूला बदलने के ऑपरेशन, कन्धा बदलने के ऑपरेशन ,बच्चो में हड्डियों के बिकार या चोट का इलाज, एक्सीडेंट के दौरान लगने वाली गंभीर चोटो का इलाज, खेलो के दौरान लगने वाली चोटो का आधुनिक तकनीक लेज़र सर्जरी द्वारा इलाज किया जाता है जिससे खिलाडी एक से दो महीने में पूर्ण रूप से पहले वाली स्थिति में आ जाता है

उन्होंने लोगो से अपील की की हड्डियों की किसी भी समस्या होने पर घबराये नहीं किसी भी अयोग्य मालिश करने वाले के पास न जाये उन्होंने कहा की अगर रोजमर्रा के काम करने में आपको मुश्किल आ रही है आपको दर्द की दवाई खानी पड़ रही है तो आप हड्डुयों के डॉक्टर से जरूर मिले, व्यायाम करे, पौष्टिक आहार ले, और स्वस्थ रहे।

झारखंड के चीफ जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान ने तीनों सिंहभूम मे न्यायालयों का सपत्नीक किया दौरा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

सरायकेला , रांची हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान ने रविवार को सरायकेला एवं चाईबासा तथा जमशेदपुर न्यायालय में पहुंचे। व्यवहार न्यायालय के सभी इजलासों के साथ कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। चाइबासा व्यवहार न्यायालय की साफ सफाई को देख कर वे काफी खुश हुए। वे झारखंड के और भी जिलों के न्यायालयो का निरीक्षण करते हुए चाइबासा पहुंचे थे। यहां की साफ-सफाई को अन्य जगहों से बेहतर बताया। इस अवसर पर चाइबासा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर समेत सभी न्यायाधीश और कर्मचारी उपस्थित थे। चीफ जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान से चाइबासा बार एसोसिएशन के सचिव फादर अगस्तीन कुल्लू ने नेतृत्व में बार के सभी पदाधिकारी और अधिवक्ताओ ने मुलाकात की।

उन्हें गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर फादर अगस्तीन कुल्लू,पवन शर्मा, दुर्योधन गोप,विमल विश्वकर्मा, अनिल सुंडी समेत बार के अधिवक्ता उपस्थित थे। मुख्य न्यायाधीश 1620 में स्थापित सरायकेला प्रिंसली स्टेट ऐतिहासिक शहर स्थित न्यायालय का सपत्नीक निरीक्षण किया। सनद रहे कि सरायकेला राजा को फांसी तक देने का अधिकार उनका राज्य का न्यायालय उन दिनों रखता

था जब देश में प्रिंसली एवं ब्रिटिश हुकुमतों का शासन हुआ करता था । जिस सरायकेला में कभी मुगल, मराठा तथा अंग्रेजों का यूनियन जैक कभी नहीं फहरा अंततः सरदार पटेल के समक्ष उसका पंचगंगा तिरंगा में विलय हुआ था जिसमें राजकीय तत्कालीन राजतंत्र का न्यायपालिका भी था । और तो और सुप्रीम कोर्ट का एक नंबर का केस भी सरायकेला स्टेट वर्सेस यूनियन ऑफ़ इंडिया रहने के कारण आज़ादी के बाद भी पटना व कट के न्यायलयों में इस शहर की तत्कालीन न्यायपालिका के कार्यों की चर्चा होती रही ।

मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि न्याय के साथ-साथ समाज और प्रकृति की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। गत शुक्रवार को चांडिल न्यायालय का भी निरीक्षण उन्होंने किया था जिसकी विधिवत्उद्घाटन पूर्व सीजेआई न्यायमूर्ति ए वी रमन्ना ने 23 जूलाई 2022 रांची आकर वर्चुएल रूप से की थी ।न्यायमुर्ती रमन्ना प्रारंभिक दिनों में एक अच्छे अधिवक्ता के साथ साथ पत्रकार भी रहे । चांडिल में न्यायालय स्थापना उस इलाके के लिये मील का पत्थर था ।

इस अवसर पर सरायकेला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह, उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, डालसा सचिव तौसीफ मेराज सहित जिला न्यायालय के सभी जज, न्यायिक पदाधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल मौजूद थे।

उधर पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर पहुंचकर न्यायालय परिसर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने तथा न्याय दिलाने में पारदर्शिता और तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एलएडीसी अधिवक्ताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने अधिवक्ताओं से समाजहित में कार्य करने और न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। जस्टिस चौहान ने न्यायालय परिसर में साफ-सफाई और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अदालत परिसर में स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहतर होनी चाहिए ताकि वादकारी और अधिवक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

पंजाब सरकार की ओर से शहीद मदन लाल ढींगरा की शहादत से संबंधित राज्य स्तरीय समारोह आयोजित

अमृतसर, 17 अगस्त (साहिल बेरी)

पंजाब सरकार की ओर से शहीद मदन लाल ढींगरा की शहादत से संबंधित राज्य स्तरीय समारोह शहीद मदन लाल स्मारक, गोल बाग में आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब के परिवहन एवं जेल मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर और लोक निर्माण एवं बिजली मंत्री पंजाब स हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने शिरकत की। सबसे पहले दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके साथ विधायक डॉ. अजय गुप्ता, मेयर श्री जतिंदर सिंह मोती भाटिया, डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी, चेयरमैन श्री करमजीत सिंह रिंटू, डिप्टी पुलिस कमिश्नर श्री आलम विजय सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्री रोहित गुप्ता, एस.डी.एम. स गुरसिमरन सिंह ढिल्लों, श्री जसकरन बंटेशा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर ने मुख्यमंत्री पंजाब स भगवंत सिंह मान की ओर से शहीद मदन लाल ढींगरा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत ही देश आज़ाद हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद और उनके परिवार राष्ट्र की अनमोल धरोहर और पूंजी हैं। आज की युवा पीढ़ी को शहीदों द्वारा दिखाए मार्ग से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लाखों देशभक्तों और शूरवीर योद्धाओं ने बलिदान दिया, जिनकी बदौलत हम आज स्वतंत्र वातावरण में साँस ले रहे हैं और इस स्वतंत्रता को बनाए रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री भुल्लर ने शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक को 5 लाख रुपये देने की स्वीकृति मौके पर ही जारी कर ट्रस्ट को पत्र सौंपा।

समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री स हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब स भगवंत सिंह मान की सरकार शहीदों द्वारा देखे गए सपनों को साकार करने के लिए वचनबद्ध है और पंजाब सरकार इन सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान ने अपना पद भी शहीद भगत सिंह के पैतृक गाँव खटकड़ कलां में ही ग्रहण किया था और उनका मुख्य उद्देश्य देश के लिए बलिदान देने वाले शूरवीरों के सपनों को पूरा करना है।

विधायक डॉ. अजय गुप्ता ने शहीद ढींगरा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हम उस नगर के निवासी हैं, जहाँ मदन लाल ढींगरा का जन्म हुआ। उन्होंने शहीद की स्मृति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम करवाने के लिए मुख्यमंत्री पंजाब का विशेष धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इन शहीदों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें स्वतंत्रता दिलाई है और हमारा भी कर्तव्य है कि इस स्वतंत्रता को बनाए रखने में अपना योगदान दें।

समारोह को संबोधित करते हुए शहीद मदन लाल स्मारक की संरक्षक और पूर्व मंत्री मैडम लक्ष्मीकांता चावला ने कहा कि शहीदों के स्थानों पर इस प्रकार के मेले हमेशा लगते रहेंगे। उन्होंने स्मारक की स्थापना के लिए अतीत में किए संघर्ष को याद किया और सरकार तथा प्रशासन द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद किया। समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए और पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति की धुनों के साथ शहीद को श्रद्धांजलि दी गई।

इससे पहले शहीद मदन लाल स्मारक की ओर से टाउन हॉल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहाँ स्थित शहीद मदन लाल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद की स्मृति में एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें 50 से अधिक व्यक्तियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक समिति की ओर से दोनों कैबिनेट मंत्रियों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित भी किया गया।

इस अवसर पर शहीद मदन लाल स्मारक के प्रधान डॉ. राकेश शर्मा, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी श्री संदीप मल्होत्रा, चेयरमैन श्री हरप्रीत सिंह आहलूवालिया, चेयरमैन श्री दिलबाग सिंह, चेयरमैन श्री सतपाल सोख्री, एस.ई. श्री संदीप सिंह, श्री अरविंदर भट्टी, मैडम माला चावला, श्री मंदीप सिंह मंना, हुसनप्रीत सिंह स्यालका, पार्षद श्री विक्की दता और अन्य हस्तियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहीदों के परिवारजन भी मौजूद थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023